तरुण छत्तीसगढ़

आम आदमी का अपना दैनिक अखबार

E-mail:
tarunpressraipur@gmail.com
tarun_press@yahoo.co.in

Web:
www.tarunchhattisgarh.in
facebook.TarunChhattisgarh
phone: 0771-2543112

■ रायपुर,मंगलवार 23 जून 2026 ■ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-9 ■ वर्ष -42 ■ अंक-086 ■ पृष्ठ 8 ■ डाक संस्करण 24 जून 2026 ■ मूल्य-2.00 रुपये

छत्तीसगढ़ में मिला डायमंड का नया खजाना

बलौदा बेलमुंडी ब्लॉक में मिले हीरे

महासमुंद,23 जून। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने देश के खनिज क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरायपाली क्षेत्र के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में किए गए वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान 200 टन खनिज सामग्री की प्रोसेसिंग से पांच हीरे प्राप्त हुए हैं। इन हीरों का कुल वजन 1.22 कैरेट है। विशेषज्ञ इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि इससे क्षेत्र में हीरे के बड़े भंडार मिलने की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं। भविष्य में बड़े पैमाने पर निवेश, राजस्व सृजन और रोजगार के नए अवसरों की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा राज्य शासन को जानकारी दी है, बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र में किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय अध्ययन तथा अन्वेषण ड्रिलिंग के आधार पर चिन्हित क्षेत्र से तकरीबन 200 टन खनिज सामग्री का बल्क सैंपल एकत्रित कर परीक्षण किया गया। प्रसंस्करण के पश्चात प्राप्त पांच हीरों में दो जेम क्वालिटी तथा तीन अन्य श्रेणी के हीरे शामिल हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक चरण में प्राप्त यह सफलता भविष्य के विस्तृत अन्वेषण कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इससे क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना, संसाधन क्षमता और संभावित भंडारों के संबंध में व्यापक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होगा। आगामी सर्वेक्षणों एवं परीक्षणों से क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का अधिक सटीक आकलन किया जा सकेगा। बता दें, बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में किए गए बल्क सैंपल परीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त हीरों को सुरक्षित अभिरक्षा में एनएमडीसी के पन्ना स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है तथा आगे की कार्यवाही नियमानुसार और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप की जाएगी।

महत्वपूर्ण उपलब्धि : साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताते हुए कहा है, प्रदेश की आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, पारदर्शी प्रबंधन और मूल्य संवर्धन आधारित औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ पहले से ही देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है और लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब हीरा संभावनाओं की पुष्टि से प्रदेश की खनिज विविधता और अधिक समृद्ध होगी तथा खनिज अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के बहुत पास पहुंचा एनडीए

नई दिल्ली,23 जून। राज्यसभा की 27 सीटों पर हुए चुनाव के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सीटों में और इजाफा हो गया है। इसके साथ ही गठबंधन उच्च सदन में दो तिहाई बहुमत के और नजदीक पहुंच गया है। हालांकि, अभी आंकड़ा दूर है, लेकिन अटकलें हैं कि ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद गठबंधन की सीटें और भी बढ़ कती है। फिलहाल, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसकी वजह तृणमूल कांग्रेस में जारी राजनीतिक संकट हो सकती है। दरअसल, पार्टी के उच्च सदन में कुल 13 सांसद थे, जिनमें से 4 इस्तीफा दे चुके हैं। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इन चारों सीटों पर भाजपा आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। इस्तीफा देने वालों में सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव, कोयल मलिक और प्रकाश बरिक हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के और भी राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि इन सांसदों की संख्या कितनी होगी। फिलहाल, पार्टी के पास 9 सांसद बचे हैं। हाल ही में 27 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनावों में एनडीए ने 19 सीटें अपने नाम की थीं। 245 सीटों वाले उच्च सदन में गठबंधन 152 पर पहुंच गया है। यहां बहुमत का आंकड़ा 164 है। अब अगर चार और सांसद जुड़ते हैं, तो गठबंधन 156 पर पहुंच जाएगा। वहीं, अगर टीएमसी में टूट जारी रहती है तो संख्या 164 के करीब पहुंच सकती है।

मोदी सरकार के इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा

नई दिल्ली,23 जून। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका छह साल का राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो गया था। कुरियन शायद केंद्र सरकार में एकमात्र ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से आते हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हुआ है। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में कहा, "भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।"

बतरा बांध में पलटी 9 ग्रामीणों से भरी नाव

सूरजपुर,23 जून। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 9 ग्रामीणों से भरी नाव बतरा बांध में पलट गई। 6 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली मगर 3 ग्रामीण लापता हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और जिला आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरु कर दिया है। दरअसल, यह पूरा मामला करंजी चौकी क्षेत्र के बतरा इलाके का है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंध के बाद भी सोमवार की रात अंधेरे में 9 लोग मछली पकड़ने के लिए बांध में गए थे। इस दौरान उनकी नाव पलट गई। घटना के बाद 6 लोगों ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान तो बचा ली, मगर 3 लोग लापता हो गए। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस जिला आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान में जुट गई है।

मजदूरों से भरी पिकअप पलटी,19 घायल

सूरजपुर,23 जून। सूरजपुर जिले में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है. हादसे में कई नाबालिग सहित 19 मजदूर घायल हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं. एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है. जानकारी के मुताबिक, घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नेवरा इलाके की है. करीब 30 मजदूरों को लेकर पिकअप आ रही थी. चालक के नियंत्रण खोने से वाहन पलट गया. मजदूरों के बीच कई नाबालिग भी मौजूद थे. सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई है. सूचना के बाद घायलों को सूरजपुर के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की निगरानी का इलाज जारी है. वहीं एक मजदूर की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर उपचार के लिए भेजा गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

28 जून को होगी हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा

रायपुर,23 जून। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को किया जाएगा। प्रथम चरण (HDEO-26) परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित होगी, जबकि पी ए टी / पी वी पी टी (PAT/PVPT-26) प्रवेश परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

125 दिन रोजगार की गारंटी, नई बायो गैस नीति और अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना भी मंजूर

वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़'' के प्रारूप का अनुमोदन

रायपुर,23 जून। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तीकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ''विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़'' के प्रारूप का अनुमोदन किया है। भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविकामूलक परिसंपत्तियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा पीएम गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्ययोजना एवं निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ''अटल आजीविका समृद्धि हाट'' योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में

सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

''अटल आजीविका समृद्धि हाट'' के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने आज "छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026" के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रतिवर्ष CBG उत्पादन की संभावना है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को राज्य नोडल एजेंसी तथा ऊर्जा विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

गड़े धन के लिए 8 लोगों की जान लेने के मामले में आरोपी बंदी

बलौदाबाजार,23 जून। बलौदाबाजार जिले के खर्वे गांव में पिछले तीन महीनों के भीतर हुई आठ लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य संदिग्ध रामसहाय जायसवाल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कसडोल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और जहर देने की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 9 प्राथमिकियां दर्ज की हैं।

ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों का आरोप है कि रामसहाय जायसवाल लोगों से छोटी-छोटी बातों या मजाक को लेकर दुश्मनी पाल लेता था। पीड़ित परिवारों के अनुसार, जिन लोगों की भी मौत हुई है, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रामसहाय द्वारा ही शराब उपलब्ध कराई गई थी। शराब पीने के कुछ समय बाद ही पीड़ितों की तबीयत बिगड़ती थी और अस्पताल ले जाने से पहले या इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस घटनाक्रम ने इलाके में भारी सनसनी फैला दी है। ग्रामीणों में यह चर्चा और भय का विषय बना हुआ है कि आरोपी कथित तौर पर 'गड़े धन' को प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास के चलते '21 लोगों की बलि' देने की योजना पर काम कर रहा था। हालांकि, पुलिस ने इस अंधविश्वास और तांत्रिक कोण पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। हाल ही में ग्रामीणों की मांग और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 7 शवों को कब्र से निकालकर उनका पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक परीक्षण कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।

उधार के पैसे बार-बार मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं : हाईकोर्ट

बिलासपुर,23 जून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि किसी को उधार दिए गए पैसे वापस मांगना, बार-बार फोन करना या कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। धमतरी के 12 साल पुराने चर्चित सरपंच सुसाइड केस में कोर्ट ने ठेकेदार अशोक कुमार वाधवानी को बड़ी राहत देते हुए 7 साल की सजा रद्द कर दी और दोषमुक्त करार दिया। मामला ग्राम बलियारा के तत्कालीन सरपंच बलराम मंडावी की आत्महत्या से जुड़ा था। सुसाइड नोट में ठेकेदार का नाम आने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि पैसे के लिए लगातार दबाव बनाने से उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कर्ज देने वाले का अपनी रकम वापस मांगना उसका वैध अधिकार है। केवल बार-बार संपर्क करना या कानूनी कार्रवाई की बात करना आत्महत्या के लिए उकसाने का सबूत नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने यह भी पाया कि मृतक बैंक के भारी कर्ज, ट्रैक्टर जब्ती और आर्थिक संकट से भी जूझ रहा था, जो मानसिक तनाव की बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही एससी-एसटी एक्ट के आरोपों को भी साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया गया।

आकाशीय बिजली से 10 गायों की मौत

बलौदा बाजार,23 जून। जिले के कसडोल विकासखंड स्थित नागेड़ी ग्राम पंचायत में सोमवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश और खराब मौसम के बीच खेत में मौजूद 10 गायें बिजली की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और पशुपालक परिवार गहरे सदमे में हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोपहर के समय क्षेत्र में तेज बारिश के साथ गरज-चमक शुरू हो गई थी। मौसम खराब होने पर गायें खेत में स्थित एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं। इसी दौरान अचानक बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से सभी मवेशियों की जान चली गई। घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को बचाव का अवसर नहीं मिल सका।

एक साथ 10 गायों की मौत से संबंधित पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पशुपालन यहां के कई परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा ने प्रभावित परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण और पशुपालक शासन-प्रशासन से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित परिवारों को जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का सर्वे कर उचित राहत राशि मंजूर करने की मांग की है।

करंट से छात्र की मौत गुस्साए ग्रामीणों ने घेरा बिजली कार्यालय

बिलासपुर,23 जून. छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर घरेलू सर्विस लाइन पर गिरने से करंट फैल गया। इस हादसे में 17 साल के छात्र की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय का घेराव कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। ग्राम पंचायत गुड़ी के देवारपारा में तकरीबन 10 बजे ओवरलोडिंग के कारण 11 केवी हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया। तार सीधे घरेलू सर्विस लाइन पर गिर गया, जिससे पूरे इलाके में करंट फैल गया। इसी दौरान गली में टहलने निकला हिमांशु साहू (17) अंधेरे के कारण टूटे हुए तार को नहीं देख सका। तार के संपर्क में आते ही उसे जोरदार करंट लगा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद रिश्तेदार उसे तत्काल सीपत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सिम्स रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही हिमांशु की मौत हो गई। सीपत पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाईटेंशन तार टूटने के बाद शॉर्ट सर्किट के कारण मौके पर घंटों तक चिंगारियां और आग की लपटें उठती रहीं। अंधेरे में उठती लपटों को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहा। घटना के दौरान पूरे मोहल्ले में अचानक हाई वोल्टेज करंट फैल गया। कई घरों में टीवी, कूलर, पंखे, फ्रिज समेत अन्य बिजली उपकरण चालू थे। तेज करंट और शॉर्ट सर्किट के कारण कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए।

23 जून : अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस- खेल को जीवन का अंग बनाना है .

विश्व में बढ़ाना है उत्कृष्टता, मित्रता, सम्मान का संदेश

आलेख .. जसवंत क्लॉडियस, वरिष्ठ स्वतंत्र खेल पत्रकार, टीवी कमेंटेटर.रायपुर.छ ग

खेलकूद के इतिहास पर नजर डालने से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत ईसा पूर्व 776 में प्राचीन ग्रीस (यूनान) के ओलंपिया शहर में हुई। ये खेल यूनानी देवताओं के पिता गॉड ज्यूस के सम्मान में प्रत्येक चार वर्ष में सम्पन्न होते थे। करीब 1100 वर्षों तक इन खेलों के आयोजन के पश्चात 393 ईस्वी में रोम के सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इन खेलों को मूर्तिपूजा से जुड़ा मानकर इन खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य के जीवन में खेलकूद की महत्ता कमी कम नहीं हुई। ईस्वी सन. 393 के पश्चात् 16वीं सदी तक खेलकूद गतिविधियों की व्यापक जानकारी नहीं है। इसके कई कारण हैं जैसे विभिन्न देशों के राजाओं, शासकों के बीच आपसी मनमुटाव होना .अपने-अपने राज्य को बचाने या उसकी सीमा के विस्तार के लिए छोटे-छोटे युद्ध में व्यस्त रहना। इनके अलावा 15 वीं सदी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा 1439 में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का अविष्कार होना। मशीनीकृत छपाई की इस तकनीक ने ज्ञान और सूचना प्रसार में पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी। इसी वजह से खेलकूद के इतिहास की कुछ जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार लोक खेल किस तरह वैश्विक हुए, खेल और खिलाड़ी व्यावसायिकता की ओर कैसे व क्यों बढ़े और खेल नियमों में किस तरह परिवर्तन हुए ?इसकी जानकारी 17वीं सदी में लिखित प्रकाशित, दस्तावेजों के अध्ययन से मिलती है.उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट हो गया कि 17वीं सदी के पहले खेल प्रतियोगिताएं बिना किसी कड़े नियम या संख्या के खेले जाते थे। इसके बाद खेल मुकाबले का स्वरूप तेजी से बदलते चला गया। 17वीं से 18वीं सदी खेलों का संस्थागतकरण और नियम निर्माण का हुआ। वस्तुतः इसी अवधि के दौरान खेलकूद को केवल मनोरंजन से ना जोड़कर शारीरिक स्वस्थता तथा मुकाबले के रूप में स्वीकार किया गया। 18वीं सदी में क्रिकेट गांवों से निकलकर धनवान और शिक्षित वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा का मुख्य आधार बना। 1599 में लान टेनिस के पूर्व रियल टेनिस के नियम का प्रकाशन हुआ। इससे 17वीं सदी में यूरोप के राजघरानों में खेलकूद के मुकाबले बढ़े। ब्रिटेन में आधुनिक घुड़दौड़ की शुरुआत हुई और स्काटलैंड में 1744 में गोल्फ के पहले लिखित नियम बनाये गए। इसी दौरान दुनिया में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल संघों का गठन आरंभ हुआ। इंग्लैंड के पब्लिक स्कूल में खेलों को पढ़ाई के साथ अनिवार्य घोषित किया गया। आज की तरह खेल एसोसिएशन के गठन की परंपरा में खेल इतिहास में सबसे पहले फुटबाल एसोसिएशन का गठन 1863 में इंग्लैंड में किए जाने की जानकारी है ,जिसने खेल को विश्वव्यापी स्वरूप प्रदान करने में मदद की। इस क्रम में आज जैसा अंतरराष्ट्रीय मैच के आयोजन की शुरुआत सबसे पहले 1844 में यूएसए विरुद्ध कनाड़ा के बीच क्रिकेट मुकाबला से हुआ। इस तरह प्राचीन ओलंपिक खेलों के 393 ईस्वी में समाप्त होने के बाद विभिन्न खेलों के लिए मैच की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। इस दौरान इन खेलों को प्राचीन ओलंपिक (ईसा पूर्व 776 से ईस्वी सन 393) की तरह फिर से आयोजित करने के लिए यूरोप के प्रबुद्ध खेलप्रेमियों में विचार विमर्श होने लगा। आपसी युद्ध व तनाव से दूर होकर मानव जाति को खेल के माध्यम से दुनिया को एक ही डोर में बांधकर आपसी प्रेम, एकता, स्वस्थ शरीर के संदेश को फैलाने के लिए 19वीं सदी में कई प्रयास हुए। सबसे पहले यूनान के इंवांगेलिस जैवास ने 1859 में एथेंस में जैपस ओलंपिया नाम के खेलों की शुरुआत की। वास्तव में यह प्राचीन ओलंपिक परंपरा को आधुनिक युग में लाने की पहला प्रयास था। इसके बाद 1860 में एक अंग्रेज .चिकित्सक विलियम पेनी ब्रूक्स ने वेनलाक ओलंपियन गेम्स की स्थापना की। ब्रूक्स की कोशिश से प्रभावित होकर फ्रांस के शिक्षाविद बैरन पियरे डी कूबर्टिन अपने साथ ग्रीक व्यापारी इंवांगेलिस जैपास के साथ मिलकर 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की। परिणाम स्वरूप 1896 में यूनान के एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक संभव हुआ। इसलिए फ्रांस के बैरन प्रियरे डी कूबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मादाता माना जाता है। 23 जून 1948 से ओलंपिक दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना ओलंपिक मूल्यों यथा उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान को संदेश को फैलाना है। अतः इस दिन ओलंपिक दिवस दौड़, खेल प्रदर्शिनिया, सेमीनार व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयेजन देशभर के ओलंपिक संघों द्वारा किया जाता है।

कुरियर,ई-कामर्स से मादक पदार्थों की आपूर्ति रोकने दिए गए निर्देश

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। भिलाई कुरियर और ई-कॉमर्स सेवाओं के जरिए प्रतिबंधित नशीली सामग्री, मादक पदार्थ और घातक हथियारों की आपूर्ति रोकने के लए दुर्ग पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त पहल शुरू की है इसी कड़ी में सोमवार को कंट्रोल रूम सेक्टर-6 दुर्ग में कूरियर कंपनियों और ई-कॉमर्स प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई बैठक में कूरियर संचालकों को स्पष्ट नेर्देश दिए गए कि किसी भी पार्सल की बुकिंग के दौरान प्रेषक और प्राप्तकर्ता का दूरा विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए इस के लिए नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की प्रति लेना आवश्यक होगा। पुलिस ने निर्देश दिया कि यदि किसी पार्सल में प्रतिबंधित नशीली दवा, मादक पदार्थ या अन्य अवैध सामग्री होने की आशंका हो तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाना और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को दी जाए। बैठक में सभी पार्सल बुकिंग केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम एक माह तक फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि इससे संदिग्ध गतिविधियों की जांच में मदद मिलेगी बैठक में नगर भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक संचालक संजय सिंह, औषधि निरीक्षक विष्णु प्रसाद साहू, गायत्री पटेल, जागेश्वरी साहू सहित सहित मौजूद थे। विभिन्न कूरियर कंपनियों के प्रतिनिधि दवाइयों के पार्सल का अलग रिकॉर्ड रखने के निर्देश औषधियों से संबंधित पार्सलों के लिए अलग रजिस्टर संधारित करने को कहा गया है। इसमें भेजने वाले और प्राप्तकर्ता का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही दवाइयों से जुड़े पार्सलों में नकद भुगतान की जगह ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की पहल बैठक में कूरियर सेवाओं के माध्यम से होने वाली संभावित अवैध गतिविधियों की रोकथाम सुरक्षा उपायों और वैधानिक जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि कूरियर नेटवर्क का दुरुपयोग कर नशे और अन्य प्रतिबंधित सामग्री की सप्लाई को रोकना प्राथमिकता है।

भारतीय मजदूर संघ की बैठक में पदाधिकारियों को सौंपा गया दायित्व

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। भारतीय मजदूर संघ जिला दुर्ग की कार्यसमिति की बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने एवं विभिन्न इकाइयों में कार्यों के प्रभावी संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान जिला मंत्री हरिशंकर चतुर्वेदी ने स्वायत्तशासी महासंघ जिला दुर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में संगठन के कार्यों, गतिविधियों तथा संगठनात्मक कार्यवाही के सुचारू संचालन हेतु शशिभूषण महांती को स्वायत्तशासी महासंघ दुर्ग जिला का प्रभारी नियुक्त किया। इसके साथ ही संगठन की मीडिया गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नवीन कुमार साहू को दुर्ग जिले का अतिरिक्त मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया।

एक नजर

पान ठेले में चोरी,दो गिरफ्तार

भिलाई, 23 जून भिलाई पान ठेला का ताला तोड़कर चोरी करने वाले दो आरोपियों को नेवई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की संपत्ति बरामद की है नेवई टीआई अनिल साहू ने बताया कि प्रार्थी ने थाना नेवई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने पान ठेला में ताला लगाकर घर चला गया था अगले दिन सुबह 7 बजे पान ठेला पहुंचने पर देखा कि ठेला का ताला टूटा हुआ था तथा गल्ले में रखे नकदी एवं दुकान में रखे सिगरेट, गुटखा, माचिस, कोल्ड्रिंक सहित अन्य सामग्री अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। रिपोर्ट पर थाना नेवई में धारा 331(4), 305 (ए) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक एवं एक नाबालिग मोटर साइकिल से घूम-घूमकर सिगरेट, गुटखा एवं कोल्ड्रिंक बेच रहे हैं। सूचना के आधार पर घेराबंदी कर संदेहियों को पकड़ा गया पूछताछ में आरोपी कार्तिक नाग उर्फ करन (21 साल) निवासी रिसाली भाठा ने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पान ठेला का ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया है।

लोगों को डराने वाला गिरफ्तार

भिलाई, 23 जून। भिलाई सुपेला थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार चापड़ लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक निगरानी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरके मैदान, सुपेला के पास एक युवक हाथ में लोहे का चापड़ लेकर लोगों में भय का माहौल बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान युवराज सोनी उर्फ बिल्ला (19 साल) निवासी कृष्णा नगर, मिनी माता चौक के रूप में हुई पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चापड़ जब्त कर आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत मामला दर्ज किया है आरोपी थाना सुपेला का निगरानी बदमाश है और उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

बाइक चोरी करने वाला गिरफ्तार

भिलाई, 23 जून। विश्वकर्मा इंजीनियरिंग शॉप के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को नंदिनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है नंदिनी पुलिस ने बताया कि प्रार्थी निवासी ग्राम पिटौरा ने थाना नंदिनी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी मोटरसाइकिल से सामान खरीदने के लिए विश्वकर्मा इंजीनियरिंग शॉप, टाउनशिप नंदिनी नगर गया था तथा मोटरसाइकिल दुकान के सामने खड़ी की थी। उसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नंदिनी नगर में धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान सोमवार को थाना नंदिनी नगर पुलिस द्वारा नाकाबंदी एवं वाहन चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान एक संदेही व्यक्ति चोरी गई मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी अशोक भारती (36 साल) निवासी ग्राम नगवा, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया।

खर्रा में लोकगीतों से सजी सांस्कृतिक संध्या

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। विकासखंड बेरला के ग्राम खर्रा में लोकधारा सांस्कृतिक मंच द्वारा गीत महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉ. परदेशीराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध गीत परंपरा को चंदैनी गोंदा के संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख ने गांवों के मंचों से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को आज भी कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। लोकधारा के अध्यक्ष राजेन्द्र साहू इस परंपरा को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर मिथिलेश साहू एवं खुमान साव ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। अध्यक्षता बाल गीतकार कमलेश चंद्राकर ने की। संचालन महेश वर्मा ने किया। कलाकारों को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। नीतीश कुमार ने आभार प्रदर्शन किया।

परामर्शदात्री समिति की बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर हुई चर्चा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। नगर निगम में परामर्शदात्री समिति की बैठक आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर आयुक्त को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान कुल 18 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों ने निगम में ठेका प्रथा समाप्त करने, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइनमैन, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट, प्लंबर एवं तकनीकी सहायकों के लिए पदोन्नति चैनल निर्धारित कर नवीन पदों की स्वीकृति की मांग उठाई। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत देयकों का तत्काल भुगतान, एलएसजीडी डिप्लोमा धारकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने, भविष्य निधि एवं नवीन अंशदायी पेंशन की राशि प्रत्येक माह कर्मचारियों के खातों में जमा कराने तथा कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने की मांग भी रखी गई। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने प्रस्तुत मांग पत्र का बिंदुवार अवलोकन कर संबंधित विषयों की समीक्षा की और आवश्यक मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

काव्य गोष्ठी में कवियों ने सुनाई एक से एक कविताएं

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। मुक्तस्वर साहित्य समिति के तत्वावधान में आयोजित पाक्षिक काव्य गोष्ठी संपन्न हुई। मुख्य अतिथि समाजसेवा रजनीकांत अग्रवाल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में समिति के संरक्षक उजियार सिंह पवार उपस्थित रहे एवं अध्यक्षता वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार गोविंद पाल ने की। बीएसपी के पूर्व महाप्रबंधक अरविंद गुप्ता की विशेष उपस्थिति रही। संयोजक सोनिया सोनी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। संचालन समिति की उपाध्यक्ष शीश लता शालू ने किया। काव्य गोष्ठी में गोविंद पाल, उजियार सिंह पवार, शीश लता शालू, शंकर भट्टाचार्य, संतोष जाटव जालौनी, विपुल कुमार सेन, संत कवि ओंकार दास, ध्रुव मजुमदार, उमा जाटव, वासुदेव भट्टाचार्य, रोबिन मुखर्जी, सोनिया सोनी, विशाल सोनी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, आकांक्षा तिवारी, सुधीर अवधिया, वसंत खेरकर, ए.आर. सिंह, ओमवीर करण तथा अरविंद गुप्ता आदि ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। मुख्य अतिथि रजनीकांत अग्रवाल ने समिति की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सराहना की। सचिव शंकर भट्टाचार्य ने आभार व्यक्त किया ।

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

आयुक्त के निर्देश पर मंगल बाजार में सफाई व्यवस्था दुरुस्त

भिलाई, 23 जून। कोहका स्थित मंगल बाजार क्षेत्र में लंबे समय से खराब सफाई व्यवस्था की शिकायत मिलने पर नगर निगम भिलाई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में व्यापक साफ-सफाई अभियान चलाया। यह शिकायत भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ की प्रदेश संवाद प्रमुख शारदा गुप्ता द्वारा आयुक्त राजीव कुमार पांडेय को दी गई थी। शिकायत के बाद आयुक्त के निर्देश पर सफाई अमला मौके पर पहुंचा और सुबह से ही पूरे मंगल बाजार क्षेत्र में सफाई कार्य कराया गया। क्षेत्रवासियों ने निगम की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया। शारदा गुप्ता ने आयुक्त एवं संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोहका हनुमान मंदिर के पीछे नालियों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि नालियों का निर्माण एवं सुधार कार्य बेहतर तरीके से किया जाए तथा सड़क को ऊंचा किया जाए, ताकि गंदा पानी सीधे नाले में प्रवाहित हो सके और जलभराव की समस्या समाप्त हो।

मुख्य नाली की सफाई के लिए बदला गया पानी का बहाव, जाम बजरी हटाने का कार्य जारी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। वृंदा नगर स्थित चैता मैदान के पास मुख्य बड़ी नाली की व्यापक सफाई का कार्य जारी है। नाली में लंबे समय से जमा बजरी, मिट्टी एवं मलबे के कारण जल प्रवाह बाधित हो रहा था, जिससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर सफाई अमले ने विशेष अभियान चलाते हुए मुख्य नाली को अस्थायी रूप से बांधकर पानी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। इससे नाली के भीतर जमा बजरी, मिट्टी एवं अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य सुगमता से किया जा रहा है। सफाई दल द्वारा खुदाई कर जाम हिस्सों को साफ किया जा रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार नालियों की नियमित सफाई और जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या में कमी आएगी तथा वर्षा ऋतु के दौरान पानी की निकासी बेहतर ढंग से हो सकेगी।

ग्राम पंचायत कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ को जिला पंचायत अध्यक्ष से मिला आश्वासन

अंवरी,23 जून। ग्राम पंचायत कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने पंचायतों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों की समस्याओं और मांगों से उन्हें अवगत कराया।

संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे वित्तीय वर्ष 2013-14 से ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में शासन एवं प्रशासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा पंचायतों के ऑनलाइन कार्यों का संचालन कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है।

श्रीराम कथा एवं मानस गायन कार्यक्रम संपन्न

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। माता कौशल्या गौरव अभियान समिति द्वारा ग्राम तारालीम में श्रीराम कथा एवं मानस गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास एवं महान कवि संत पवन दीवान के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर माता कौशल्या गौरव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉ. परदेशीराम वर्मा ने संत पवन दीवान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान श्रीराम की माता माता कौशल्या के गौरव को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लगातार आयोजन एवं प्रवचन किए। समिति उसी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में ग्राम लवातारा के कुशल कला दल ने आकर्षक मानस गायन प्रस्तुत किया। सरस मानस कलाकार राजेन्द्र साहू ने छत्तीसगढ़ महतारी गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। वहीं बोरसी गांव के मानस मर्मज्ञ मनहरण लाल साहू ने छत्तीसगढ़ के भांजे श्रीराम विषय पर अपने उद्बोधन से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रस्तुति के पश्चात कलाकारों का ग्रामीणों द्वारा शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध रामायणी शेर अली को भी श्रद्धापूर्वक याद किया गया।

माध्यमिक शाला भखारा में शाला प्रवेश उत्सव मनाया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भखारा, 23 जून। स्कूल शिक्षा विभाग एवं शासन के निर्देशानुसार विद्यालयो में नवप्रवेशित बच्चों के स्वागत के उद्देश्य से शास माध्य शाला भखारा के शाला परिवार कि ओर से विद्यालय में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को मुंह मीठा कराकर एवं तिलक लगाकर तथा पुस्तक कॉपी भेट कर शाला एवं नवीन कक्षा में प्रवेश कराया गया। उक्त प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पंचायत भखारा के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति हरखचंद जैन, नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद , अविनाश गौर पार्षद श्री मेघनाथ साहू , पार्षद अंजू साहू , शाला के प्रधान पाठक श्रीमती उषा साहू , शिक्षक मिकेश साहू, शिक्षक शिवमोहित साहू , रुद्रप्रकाश पुरी अमजद खान , मोहित कुमार एवं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और वरिष्ट पत्रकार मेहत्तर राम साहू , कंप्यूटर संचालक भोजराज देवांगन भखारा , विद्यालय प्रबंधन का समिति के पालक गण उपस्थित रहे।

लोहा चोरी के मास्टर माइंड संजय सिंह के लॉकर से तीन करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जब्त

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 23 जून। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में ब्लू डस्ट की आड़ में 250 टन लोहा स्क्रैप चोरी के मास्टर माइंड आरोपी संजय सिंह के लॉकर से पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के आभूषण एवं लगभग 03 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं वहीं घटनास्थल का पुनर्निर्माण कर साक्ष्य संग्रहण किया गया तथा स्क्रैप परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त किए गए हैं मुख्य आरोपी संजय सिंह समेत तीन आरोपी पुलिस रिमांड पश्चात न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं पुरानी भिलाई टीआई अंबर सिंह भारद्वाज ने बताया कि ने बताया कि विवेचना के दौरान मुख्य फरार आरोपी संजय सिंह को देवरिया (उत्तरप्रदेश) से 16 जून को गिरफ्तार कर 7 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त की गई थी। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान आरोपी संजय सिंह (48 साल) निवासी खुर्सीपार से गहन पूछताछ करने पर अमित शर्मा उर्फ कैलाश शर्मा (45 साल) निवासी सेक्टर-02 एवं आकाश कुमार सिंह (29 साल) निवासी हाउसिंग बोर्ड जामुल की संलिप्तता सामने आई, जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया पूछताछ के दौरान आरोपियों ने संगठित रूप से बीएसपी से चोरी किए गए लोहे को अवैध रूप से बेचने तथा प्राप्त धनराशि को विभिन्न संपत्तियों एवं आभूषणों में निवेश किए जाने संबंधी जानकारी दी। मुख्य आरोपी संजय सिंह के लॉकर से लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के आभूषण एवं लगभग 03 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जप्त किए गए हैं। आरोपी अक्षय कुमार से भी संपत्ति संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। आरोपियों द्वारा अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी पृथक रूप से की जाएगी वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों को खुर्सीपार गेट से एसएमएस-3 तक मुख्य घटनास्थल ले जाकर घटनास्थल का पुनर्निर्माण कराया गया तथा महत्वपूर्ण साक्ष्य संग्रहित किए गए साथ ही चोरी के लोहे के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त किए गए हैं पूछताछ में संजय सिंह ने बीएसपी में चोरी का तरीका बताया सूत्रों से पता चला है कि पुलिस की पूछताछ में मुख्य किरदार संजय सिंह ने बीएसपी में चोरी का तरीका बताया और बीएसपी व सीआईएसएफ के अधिकारियों-जवानों के नाम भी कबूले। इसी दौरान उसने आकाश सिंह का नाम बताया जो चोरी का स्क्रैप राजनीतिक संरक्षण में खपाता था। पुलिस ने तत्काल आकाश को गिरफ्तार कर लिया उससे मिली जानकारी से संगठित अपराध की कड़ियां जोड़ने में मदद मिली।

भाजपा सरकार में बढ़े अवमानना के मामले, अकबर ने राज्यपाल को कराया अवगत

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भाटापारा 23 जून। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधि मंत्री मो.अकबर ने राज्य की भाजपा सरकार के दौरान कोर्ट की अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफकोर्ट) के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपनी इस चिंता से राज्यपाल रमेन डेका को भी अवगत कराया है। राज्यपाल को भेजे गए एक पत्र में अकबर ने कहा- अवमानना के मामलों में वृद्धि यह संकेत देती है कि कई स्तरों पर न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती जा रही है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि राज्य शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने तथा न्यायालयीन आदेशों के प्रभावी अनुपालन नियमित समीक्षा एवं अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करेंगे। अवमानना प्रकरणों का आधिकारिक ब्योरा भी उन्होंने जारी किया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना से जुड़ी याचिकाओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। हाईकोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में 1,010 अवमानना याचिकाएं दायर हुई थीं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,884 तक पहुंच गई। यह चार वर्षों में करीब 87 प्रतिशत की वृद्धि है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2021 के बाद से अवमानना याचिकाओं का ग्राफ सामान्य तौर पर ऊपर की ओर रहा है। वर्ष 2022 में 1,279 मामले दर्ज हुए। इसके बाद 2023 में मामूली गिरावट आई और संख्या 1,185 पर पहुंच गई, लेकिन अगले दो वर्षों में फिर तेजी दर्ज की गई। वर्ष 2024 में कुल 1,504 अवमानना याचिकाएं दायर हुईं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,884 हो गई। यह 2016 से उपलब्ध आंकड़ों में किसी भी वर्ष का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2025 में दर्ज मामले 2021 की तुलना में 874 अधिक रहे। पिछले पांच वर्षों के रिकॉर्ड में 2023 एकमात्र ऐसा वर्ष रहा, जब मामलों में साल-दर-साल कमी दर्ज हुई। 2022 के मुकाबले 94 कम याचिकाएं दायर हुईं। इसके बाद 2024 में 319 और 2025 में 380 मामलों की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि 2021 से 2025 के बीच अवमानना याचिकाओं में कुल वृद्धि केवल संख्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि वृद्धि की रफ्तार भी तेज हुई है। 14 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष के पहले छह महीनों में 744 अवमानना याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। यह संख्या वर्ष के अंत तक और बढ़ेगी। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2025 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं। अदालत की अवमानना से जुड़े मामले आमतौर पर तब सामने आते हैं, जब किसी पक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने, पालन में देरी करने या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया जाता है। ऐसे मामलों में प्रभावित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाता है।

आंकड़ों में दिखता रुझान

वर्ष	दायर अवमानना याचिकाएं
2021	1,010
2022	1,279
2023	1,185
2024	1,504
2025	1,884
2026	744

14 जून 2026 तक की स्थिति में

इन आंकड़ों से यह साफ दिखाई देता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाओं की संख्या लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। विशेष रूप से 2024 और 2025 में आई तेज बढ़ोतरी इस बात का संकेत देती है कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन से जुड़े विवाद बड़ी संख्या में अदालत तक पहुंच रहे हैं। आंकड़े भले ही इसके कारणों की व्याख्या नहीं करते, लेकिन यह जरूर बताते हैं कि अवमानना याचिकाएं अब हाईकोर्ट के समक्ष एक महत्वपूर्ण श्रेणी के मामलों के रूप में उभर रही हैं।

एक नजर

एआई+ ने लॉन्च किए नोवा-2 नियो 5जी और नोवा-2 प्रो 5जी स्मार्टफोन

रायपुर 23 जून। एआई+ स्मार्टफोन ने अपनी नोवा सीरीज़ का विस्तार करते हुए नोवा 2 नियो 5जी और नोवा 2 प्रो 5जी लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इन डिवाइसेस को पारंपरिक लॉन्च इवेंट के बजाय 'इंडियाज़ गॉट नोवा' कार्यक्रम के जरिए पेश किया, जिसे कॉमेडियन समय रैना और टेक विशेषज्ञ राजीव माखनी ने होस्ट किया। कंपनी ने लॉन्च से पहले ओपन रिव्यू प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें रिव्यूअर्स, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को स्मार्टफोन का परीक्षण करने का अवसर दिया गया। एआई+ का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों के बीच पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाना है। नोवा 2 नियो 5जी में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल कैमरा और 6000द्बद्ध बैटरी दी गई है। वहीं, नोवा 2 प्रो 5जी में डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट, 144॥5 डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल एआई कैमरा और 33ड्ड फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे। नोवा 2 नियो की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये और नोवा 2 प्रो की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये रखी गई है।

स्टार प्लस और अनिल कपूर दे रहे हैं टीवी पर आने और 1 करोड़ रुपये जीतने का मौका

रायपुर 23 जून। देशभर में ऐसे लाखों लोग हैं, जो कभी न कभी टेलीविज़न पर आने और अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर दिखाने का सपना देखते हैं। अब यह सपना सच होने का अवसर लेकर आया है स्टार प्लस का नया रियलिटी शो 'इंडिया के टॉप 1 परसेंट'। अभिनेता अनिल कपूर द्वारा होस्ट किए जा रहे इस शो के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। यह शो प्रतिभागियों की समझ, लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और क्विक थिंकिंग की परीक्षा लेगा। प्रतियोगियों को विभिन्न चुनौतियों और सवालों के माध्यम से अपनी मानसिक क्षमता साबित करनी होगी। शो का उद्देश्य देश के सबसे तेज़ और होशियार दिमागों की पहचान करना है। सबसे खास बात यह है कि शो के विजेता को 1 करोड़ रुपये की आकर्षक प्राइज मनी दी जाएगी। छात्र, प्रोफेशनल, होममेकर, उद्यमी या किसी भी क्षेत्र से जुड़े लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ऐसे में जो लोग खुद को देश के टॉप 1 प्रतिशत बुद्धिमान लोगों में मानते हैं, उनके लिए यह अपनी प्रतिभा दिखाने और पहचान बनाने का बेहतरीन मौका है। इच्छुक प्रतिभागी क्यूआर कोड स्कैन करके या आधिकारिक रजिस्ट्रेशन लिंक https://starplus.jiostar.com/indiaketoponepercent/ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह शो न केवल मनोरंजन का नया अनुभव देगा, बल्कि प्रतिभाशाली लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मंच भी प्रदान करेगा।

धोखाधड़ी से बचने आरटीओ चालान भुगतान के लिए वेबसाइट का उपयोग

बलौदाबाजार 23 जून। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। छत्तीसगढ़ राज्य में आरटीओ ई-चालान से संबंधित स्कैम सामने आ रहे हैं, जिसमें विभागीय वेबसाईट का क्लोन पेज बनाकर ई-चालान के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने के बारे में छदम तरीके से डराने वाले संदेश के माध्यम से लिंक भेजकर आम लोगों की व्यक्तिगत जानकारी और जमा खाते से पैसे चुरा लेते है। ऐसे धोखाधड़ी से बचने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग जरुरी है। परिवहन विभाग द्वारा ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए विभाग की आधिकारिक वेब साईट का ही उपयोग किये जाने की अपील की गई है।अपने वास्तविक चालान की जांच करने के लिए या आरटीओ चालान के भुगतान के लिए अधिकारिक विभागीय वेबसाईट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाकर ई-चालान के पेज पर क्कड्ड4 ह्रठ्ठद्बद्वठ्ठद्ग पर क्लिक कर चालान नंबर एवं कैप्चा कोड डालकर त्रश्वञ्ज ष्टश्चञ्चद्धठ्ठ पर क्लिक कर मोबाईल ओटीपी डालकर चालान विवरण संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुलिस एवं परिवहन के प्रवर्तन अमले द्वारा जब भी e-Challan किया जाता है, पंजीकृत मोबाईल में संबंधित को टेक्स्ट मैसेज अधिकारिक वेबसाईट https://echallan.parivahan.gov.in के माध्यम से ही भेजे जाते हैं।

श्रमिक पंजीयन कार्ड में आधार के अनुसार संशोधन कराना अनिवार्य

बलौदाबाजार, 23 जून। श्रम विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के पूर्व पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक पंजीयन कार्ड में आधार अनुरूप संशोधन कराया जाना अनिवार्य है। आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं कि श्रमिक के पंजीयन अभिलेख में दर्ज मूल विवरण (नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाईल नंबर आदि) आधार अभिलेख में उपलब्ध विवरण के अनुरूप हो। ई-केवाईसी प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से श्रमिक पंजीयन विवरण के संशोधन एवं अद्यतन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हैं। जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में पंजीकृत लगभग 40579 श्रमिकों के आधार के अनुरूप श्रमिक पंजीयन कार्ड में संशोधन किया जाना हैं। आधार के अनुरूप डाटा बेस में संशोधन आवेदन करने हेतु सी.एस.सी. को अधिकृत किया गया हैंजिसमें श्रमिक स्वंय जाकर अपने आधार कार्ड के अनुरूप संशोधन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव में 510 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 333 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

राजनांदगांव, 23 जून। किसानों की समृद्धि, गांवों का विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में विकास और सुशासन के नए अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले को 510 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक की लागत के 333 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने शिवनाथ नदी के मोहारा मेला स्थल से ऑक्सीजन जोन तक सस्पेंशन ब्रिज, ईरा एनीकट निर्माण एवं संरक्षण कार्य, कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग निर्माण तथा घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजनांदगांव जिले ने फसल चक्र परिवर्तन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। यहां किसानों को पारंपरिक खेती के साथ दलहन, तिलहन एवं अन्य लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन अथवा अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और अन्य किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को खेती के लिए आवश्यक खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुशासन को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने सीएम हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की है, जहां नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कराकर निर्धारित समय-सीमा में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के माध्यम से आय, जाति, निवास सहित विभिन्न विभागों की 400 से अधिक सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के माध्यम से जरूरतमंद उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के जरिए आम नागरिकों को बिजली बिल से दीर्घकालिक राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों का निर्माण नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप आवास, बिजली, पानी, सड़क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि फसल चक्र परिवर्तन एवं जल संरक्षण के लिए किसानों एवं ग्रामवासियों में जागृति लाने के लिए पद्मश्री फूलबासन बाई यादव महिला स्वहसहायता समूह की महिलाओं के साथ अप्रैल-मई की दोपहरी में यात्रा करती रही और एक अद्भुत कार्य किया गया। राजनांदगांव में फसल चक्र परिवर्तन होने से फसल विविधीकरण के लिए किसान प्रेरित हुए हैं।

कराते बेल्ट ग्रेडिंग क्लास में बच्चों और युवाओं को दी नवीन कानून एवं नशामुक्ति की जानकारी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार 23 जून। पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में पलारी पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान; आत्मरक्षा के साथ-साथ कानूनी रूप से सशक्त बन रहे बच्चे पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिनांक 21.06.2026 को सतनाम भवन, बालसमुंद रोड, पलारी में आयोजित 'कराते बेल्ट ग्रेडिंग क्लास' के दौरान थाना पलारी पुलिस द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ?इस कार्यक्रम में कराते सीख रहे बच्चों, युवाओं और उनके पालकों को देश में लागू हुए नवीन कानूनों के बारे में अत्यंत सरल और व्यावहारिक भाषा में जानकारी दी गई। थाना प्रभारी पलारी ने बताया कि नए कानूनों का उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित न्याय देना और उनकी सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना है। विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम के दौरान पलारी पुलिस ने उपस्थित युवाओं और बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। पुलिस टीम द्वारा बताया गया कि नशा न केवल स्वास्थ्य को बर्बाद करता है, बल्कि अपराधों का एक मुख्य कारण भी बनता है। उपस्थित सभी बच्चों और नागरिकों को जीवन में कभी भी नशा न करने और अपने आस-पास के समाज को भी नशामुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की गई। आत्मरक्षा के साथ कानूनी ज्ञान भी जरूरी- ?थाना प्रभारी पलारी द्वारा कराते सीख रहे बच्चों की हौसला अफ्जाई करते हुए कहा गया कि आत्मरक्षा सीखने के साथ-साथ देश के कानून की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। इससे बच्चे सजग, जिम्मेदार और सुरक्षित नागरिक बन सकेंगे। ?इस दौरान कराते क्लास के मुख्य प्रशिक्षक, बड़ी संख्या में बेल्ट ग्रेडिंग में भाग लेने वाले छात्र-छात्राएं, उनके अभिभावक तथा थाना पलारी का पुलिस स्टाफउपस्थित रहा। पालकों और स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस अनूठी और सकारात्मक पहल की जमकर सराहना की है।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस ने न्याय संहिता कैंपेन चलाकर लोगों को किया जागरूक

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 23 जून। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर, राष्ट्रीय एकता दिवस 2026 के तहत जिला पुलिस की अनूठी पहल- 'न्याय संहिता कैंपेन' के तहत छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों को किया गया जागरूक- पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22.06.2026 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के गौरवशाली अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस 2026 के तहत जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में 'न्याय संहिता कैंपेन' का वृहद आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, महिलाओं और युवा पीढ़ी को नए कानूनों तथा सुरक्षात्मक उपायों के प्रति जागरूक करना है।

स्कुलों और गांवों में पहुंचे पुलिस अधिकारीः- इस विशेष अभियान के तहत जिले की विभिन्न पुलिस टीमों ने सीधे जनता और विद्यार्थियों से संवाद कियाः थाना हथबंद की टीम द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केसला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौकी करहीबाजार की टीम ने हाई स्कूल करहीबाजार में छात्र-छात्राओं के बीच पहुँचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। थाना गिधौरी की टीम द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, टुण्डरा में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसके साथ ही थाना कसडोल की टीम ने ग्राम कोट में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संपर्क साधा।

नवीन न्याय संहिता के तहत मिले अधिकारों की, दी गई जानकारीः- कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और बच्चों को बताया कि देश की नई कानून व्यवस्था (भारतीय न्याय संहिता) अब 'दंड' देने के बजाय नागरिकों को 'न्याय' देने की भावना पर आधारित है। इसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जागरूक किया गयाः ई-एफआईआर अब कोई भी नागरिक थाने जाए बिना ऑनलाइन माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकता है।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना अंतर्गत आंनलाइन आवेदन 3 जुलाई तक

बलौदाबाजार, 23 जून। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। श्रम विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में निर्माण कार्य से पंजीकृत निर्माण श्रमिको के मेधावी एवं प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित कि जा रही हैं। योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियो से ऑनलाईन आवेदन 3 जुलाई 2026 तक आमंत्रित की गई हैं। मण्डल अंतर्गत 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो संतान जो कक्षा छठवी में प्रवेश लेने वाले हैं,ऐसे विद्यार्थियो का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाता हैं। योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु चयनीत बच्चो को कक्षा छठवीं से बारहवीं तक प्रदेश के श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्रदाय की जायेगी। आवेदन हेतु विभाग के वेबसाईट नजदीकी श्रम संसाधन केन्द्र/च्वाईस सेंटर अथवा जिला श्रम कार्यालय के कक्ष क्रमांक 117 में आकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन 1 वर्ष पूर्व हो चुका हैं वे आवेदन करने हेतु पात्र है।

जेल में निरुद्ध की आयु के सत्यापन के लिए किया गया जिला जेल का निरीक्षण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार,23 जून। सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुक्रम में आयु सबंधित दस्तावेज के अभाव मे 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के निरूद्ध रहने की संभावना एवं प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक त्रैमास में जेलों का निरीक्षण विषेज्ञ समिति के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 के पथम त्रैमास हेतु कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के नेतृत्व में सोमवार को जिला जेल बलौदाबाजार का निरीक्षण किया गया। विषेज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा जेल में निरूद्ध 430 बंदियों में से प्रथम दृष्टया में 18 वर्ष से कम आयु के लग रहे बालकों से बैरको में जाकर बातचीत की गई जिसमे से एक निरूद्ध ने अपनी जन्मतिथि 09.10.2008 एवं जेल में दो माह से निरूद्ध होने की जानकारी प्रदान की । समिति ने संबंधित मामलों में जन्मतिथि का सत्यापन कर बालक के प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड मे स्थानांतरित किए जाने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही बच्चों के संरक्षण एवं उनके हितों की रक्षा के लिए आगे की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की बात कही गई। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक अभिषेक मिश्रा ने जिला जेल बलौदाबाजार में बंदियों के लिए प्रारंभ किए गए नवाचार की जानकारी प्रदान की। निरीक्षण दल में किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य प्रवीण अग्रवाल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास महंत एवं विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी मेघा शर्मा शामिल रहे।

योग और राजयोग के संग मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और स्वस्थ जीवन का दिया संदेश

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

नगरी 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र नगरी में योग, ध्यान और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई-बहनों, नगर के गणमान्य नागरिकों एवं योग प्रेमियों ने सहभागिता कर स्वस्थ और संतुलित जीवन का संकल्प लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ परमपिता शिव परमात्मा की स्मृति में दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात योगाचार्य सचिन साहू, कुमारी किरण साहू एवं रमेश साहू ने उपस्थितजनों को विभिन्न योग क्रियाओं और प्राणायामों का अभ्यास कराया। योग प्रशिक्षकों ने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी जैसे प्राणायामों के साथ सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, ताड़ासन, भुजंगासन और धनुरासन सहित अनेक योगासनों का अभ्यास करवाया। गीत-संगीत के माध्यम से योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उपस्थित राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी भावना बहन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदूषण, असंतुलित खानपान, तनावपूर्ण जीवनशैली और बढ़ती उम्र के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए भी मेडिटेशन अत्यंत आवश्यक है। योग और राजयोग के समन्वय से व्यक्ति तनावमुक्त, सकारात्मक और ऊर्जावान जीवन जी सकता है। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी कमलेश्वरी बहन सहित संस्था के अनेक भाई-बहन और नगर के नागरिक उपस्थित रहे। योगाभ्यास एवं ध्यान सत्र के समापन के बाद सभी ने प्रभु प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम का आनंद लिया। योग, प्राणायाम और राजयोग के संदेश के साथ आयोजित यह कार्यक्रम स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन की प्रेरणा देकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

बड़ा देश है इसलिए चुनौती बड़ी होती है

हमारे देश में कोई भी समस्या हो उसे हल करना इसलिए बड़ी चुनौती होती है कि हमारा देश बड़ा है। देश बड़ा होने के कारण कही न कहीं दिक्कत आती है और लगता है कि हमारे देश में किसी समस्या को हल करना आसान काम नहीं है। दूसरे देशों के लिए वही समस्या छोटी होती है और उनके लिए समस्या का समाधान आसान होता है। हमारे यहां एक बड़ी समस्या तो जनसंख्या भी है। हमारे देश की जनसंख्या ही कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। जनसंख्या कम हो तो कोई भी व्यवस्था ठीक से की जा सकती है लेकिन जनसंख्या लाखों,करोड़ों में हो तो एक जैसी व्यवस्था सभी जगह करना आसान नहीं होता है। हमारे देश में पेपर लीक एक ऐसी समस्या है जिसे अब तक माना यही जाता रहा है कि इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि हर बार परीक्षा के पहले ही किसी न किसी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते है या कर दिए जाते हैं इसके लिए सरकार को दोष दिया जाता है। चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार यह सच है कि जिम्मेदारी उनकी है परीक्षा ठीक से हो। परीक्षा के पहले पेपर लीक न हो, परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो। गंभीरता से सोचा जाए तो यह हर परिवार,हर समाज व हर संस्था से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी भी है कि परीक्षा के पहले पेपर लीक न हो। देश व समाज में कहीं पेपर लीक कराने की इच्छा होती है इसलिए पेपर लीक होता है। पेपर लीक इसलिए भी होता है क्योंकि कुछ माता पिता व कोचिंग सेंटर वाले चाहते हैं कि उनके बच्चे आसानी से गलत तरीके से परीक्षा पास कर लें। कोई भी बच्चा आसानी से परीक्षा तब ही पास कर सकता है जब उसे पता हो कि परीक्षा में क्या प्रश्न आने वाले हैं। बच्चों को प्रश्न पत्र मुहैया कराने के लिए परिवार व कोचिंग सेंटर वाले पैसा खर्च करते हैं। जब पेपर लीक करने के किसी को लाखों रुपए मिलते हैं तो उसे पेपर लीक करना फायदे का काम लगता है। हर कोई जब अपना फायदा देखता है तो इससे परीक्षा का हर आयोजन किसी काम का नहीं रह जाता है। पेपर सेट करने वाले से लेकर पेपर सेंटर तक पहुंचाने वाले, पेपर लिफाफा खोलने वाले कई लोग लाखों रुपए के लालच में सैकड़ों लोगों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। पेपर लीक होता है तो थोड़े लोगों को फायदा होता है लेकिन जब पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया है और दूसरी बार परीक्षा होती है तो लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी होती है। करोड़ो रुपए का सबको नुकसान होता है समय नष्ट होता है, फिर से परीक्षा कराने से परीक्षा देने वाले छात्रों को अलग परेशानी होती है, कई छात्र निराश होकर परीक्षा नहीं देना चाहते हैं कई छात्र दोबारा अच्छी तैयारी नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। देश में कई परीक्षा के पेपर लीक होते रहे हैं, इससे मान लिया गया था कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वह ऐसी व्यवस्था नही कर सकती कि पेपर बगैर लीक हुए परीक्षा हो सके। इस बार नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसका आयोजन केंद्र सरकार को फिर से कराना पड़ा तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है, परीक्षा की व्यवस्था को बदल कर भी देख लिया गया है हर बार परीक्षा की व्यवस्था करने वालों से पेपर लीक करने वाले हमेशा तैयारी में आगे रहते है। यानी परीक्षा की व्यवस्था से ज्यादा चुस्त व्यवस्था पेपर लीक कराने वालों की होती है। वह कही न कहीं से पेपर लीक करा ही लेते हैं। मोदी सरकार की एक खासियत है इसे तो मानना पड़ेगा कि वह जब ठान लेती है कि कोई काम करना है तो वह करके दिखाती है, इस बार मोदी सरकार के सामने पेपर लीक नहीं होने देना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए परीक्षा के कई दिन पहले से सारी व्यवस्था की गई। पेपर के कई सेट बनवाए गए। पेपर सेट होने के बाद उसे सेना की सुरक्षा में केंद्रों तक पहुंचाया गया। पेपर जिन बक्शों में भेजा गया वह भी ऐसे थे कि उन्हें हर कोई नहीं खोल सकता था। नीट की परीक्षा देने वालों के लिए बसों व रेलों की व्यवस्था की गई, परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के कई दिन पहले से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, कोई तकनीक के जरिए नकल न कर सके इसके लिए जैमर लगाए गए। लाखों लोगों को पेपर लीक न होने देने के लिए लगाया गया और 21 जून की नीट की परीक्षा बिना पेपर लीक के हो गए हैं। कई सेंटरों में छिटपुट गड़बड़ी करने की कोशिश की गई लेकिन उनको समय पर पकड़ लिया गया। यानी सरकार ने परीक्षा के लिए जितनी कड़ी व्यवस्था की थी उसे फेल करने के लिए भी कई जगह प्रयास किए गए लेकिन पूरे देश में नीट की परीक्षा ठीक से हो गई इसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए कि उसने कहा इस बार परीक्षा की व्यवस्था ठीक होगी और ऐसा उसने करके दिखाया है। पहली बार कुछ परिवार व कोचिंग सेंटर वाले परीक्षा से पहले पेपर लीक कराने में असफल रहे हैं। कुछ परिवार व कोचिंग सेंटर वाले इस बार इसलिए भी परीक्षा लीक कराने से डरे हैं कि पिछली बार जो पेपर लीक हुए उसमें बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई होने से भी कुछ परिवार व कोंचिंग सेंटर वालों ने पेपर लीक कराने से तौबा की है कि उससे उनकी बदनामी होती है और उनके कोचिंग बंद होने की नौबत आती है। सरकार को पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें शामिल कोचिंग सेंटर को तो तत्काल बंद कराना चाहिए। देश के हर राज्य में कोचिंग सेंटर छात्रों की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए ठीक है लेकिन अपनी कोंचिग सेंटर को ज्यादा सफल बताने के लिए पेपरलीक कर पास कराने वाली कोंचिग एक तरह का गंभीर अपराध है और केंद्र व राज्य सरकार को कोचिंग माफिया के सफाए के लिए कोचिंग सेंटर खोलने के नियम कड़े बनाने चाहिए. नियम इतने कड़े होने चाहिए कि कोई भी कहीं भी कोंचिग सेंटर न खोल सकें। उसकी नियमित जांच होनी चाहिए कि वहां पढ़ाई की ठीक व्यवस्था है या नहीं हैं। जब तक कोचिंग माफिया हैं तब तक हर परीक्षा के पहले पेपर लीक की आशंका बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने इस बार चुनौती थी इसलिए उसने सेना का प्रयोग भी परीक्षा के लिए किया लेकिन हमेशा ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। इसलिए पेपर लीक करने वाले तंत्र को ही नष्ट करना होगा।

अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा एवं दान प्रकरण

आस्था, जवाबदेही और पारदर्शिता की अग्निपरीक्षा

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े आध्यात्मिक स्थलों में गिने जाने वाले तीर्थ, मंदिर,मठ, गुरुद्वारे,मस्जिदें और चर्च केवल आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के कारण विशाल आर्थिक संस्थान भी बन चुके हैं। ऐसे में यदि कहीं दान राशि, चढ़ावे या ट्रस्ट निधियों के उपयोग को लेकर वित्तीय अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी अथवा जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं,तो उससे केवल धन का नुकसान नहीं होता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास को भी गहरी ठेस पहुँचती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यही कारण है कि अब समय की मांग है कि सभी आध्यात्मिक एवं धार्मिक संस्थानों के लिए आय-व्यय का नियमित सार्वजनिक लेखा-जोखा, स्वतंत्र ऑडिट, डिजिटल भुगतान व्यवस्था वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट का प्रकाशन तथा प्रचलित कानूनों, नियमों और विनियमों का कठोर अनुपालन अनिवार्य बनाया जाए। आस्था और प्रशासन का संतुलन तभी संभव है जब श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए प्रत्येक रुपये के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी दिखाई दे। वित्तीय शुचिता केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि धर्मस्थलों की नैतिक प्रतिष्ठा और समाज के विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी कसौटी भी है।

साथियों अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,बल्कि करोड़ों भारतीयों और विश्वभर के रामभक्तों की सदियों पुरानी आस्था,संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर में चढ़ावे,दान राशि, सोना-चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कथित गबन,वित्तीय अनियमितताओं,शिलाओं के गायब होने, कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोपों तथा जांच एजेंसियों की सक्रियता से जुड़ी खबरों ने पूरे देश में व्यापक चर्चा और चिंता पैदा कर दी है। यह मामला केवल धन के कथित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर व्यवस्था पर रखा है। सोमवार 22 जून 2026 की शाम 6 बजे तक उपलब्ध घटनाक्रमों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, और मंदिर ट्रस्ट ने दान प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सख्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अंतिम सत्य अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना अभी उचित नहीं होगा।

साथियों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विवाद की शुरुआत उन आरोपों से हुई जिनमें मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की बात कही गई। आरोपों में नकदी, सोना- चांदी और अन्य चढ़ावे के लेखा-जोखा पर प्रश्न उठाए गए। इसके बाद मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तरपर चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।एसआईटी में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और वित्तीय अधिकारियों को शामिल किया गया तथा उसे सीमित समय में प्रारंभिक एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया।जांच के दौरान अनेक दावे सामने आए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने धन के प्रवाह (मनी ट्रेल), दान पेटियों की निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की भूमिका, रिकॉर्ड मिलान और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

जांचकर्ताओं ने उन लोगों से पूछताछ की जिनके नाम प्रारंभिक आरोपों में सामने आए थे। एसआईटी का उद्देश्य यह पता लगाना था कि यदि कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो वह किस स्तर पर हुई, धन कहां गया, किन खातों में गया और उसकी अंतिम जिम्मेदारी किसकी बनती है। साथियों, 22 जून 2026 तक सामने आई रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कुछ मीडिया स्रोतों में दावा किया गया कि जांच टीम ने अनेक दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं तथा कुछ निगरानी संबंधी कमियों और प्रशासनिक खामियों की पहचान की है। कुछ रिपोर्टों में सीसीटीवी फुटेज के अभाव या कथित छेड़छाड़ तथा निगरानी व्यवस्था की कमजोरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि केवल आधिकारिक रिपोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी।एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर जो सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से सामने आई हैं, उनके अनुसार जांच दल ने दान प्रबंधन प्रणाली में कई संरचनात्मक कमजोरियों की ओर संकेत किया है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कुछ महत्वपूर्ण अवधि की निगरानी सामग्री उपलब्ध नहीं थी तथा प्रशासनिक जवाबदेही की श्रृंखला को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कथित रूप से जांच दल ने व्यापक प्रशासनिक सुधारों, बेहतर निगरानी व्यवस्था और वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने की सिफारिशें भी की हैं। हालांकि एसआईटी की अंतिम औरr आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी होने के बाद ही इन निष्कर्षों की प्रमाणिक स्थिति स्पष्ट होगी।

साथियों, इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वयं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपों को गंभीरता से लिया और जांच का समर्थन किया। ट्रस्ट ने पहले भी कहा था कि नियमित ऑडिट और वित्तीय समीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई है, फिर भी यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट का कहना रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।कथित दान अनियमितताओं के बाद ट्रस्ट द्वारा दान प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दान पेटियों की निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग, लेखांकन प्रक्रिया, बहुस्तरीय सत्यापन, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा वित्तीय ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की गुंजाइश न्यूनतम रहे और श्रद्धालुओं का विश्वास अक्षुण्ण बना रहे।

साथियों, इस प्रकरण में न्यायिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की हैं।यह मामला 18 जून 2026 को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था। समयाभाव के कारण उस दिन विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी और मामले को 22 जून 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया था।22 जून की सुनवाई का प्रमुख केंद्र यह था कि क्या मामले में स्वतंत्र जांच एजेंसी, विशेष रूप से सीबीआई जांच अथवा कैग ऑडिट की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अधिकतम पारदर्शिता आवश्यक है। दूसरी ओर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों का रुख यह रहा कि एसआईटी जांच पहले से जारी है और उसके निष्कर्ष सामने आने दिए जाने चाहिए। अंतिम न्यायिक निर्देशों और आदेशों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मामला केवल वित्तीय नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी सटीकता से जुड़ा हुआ है।

साथियों, राजनीतिक स्तरपर भी इस प्रकरण ने तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। विपक्षी दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार और ट्रस्ट से जुड़े पक्षों ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि सत्य सामने आएगा और लोगों को जांच पूरी होने तक धैर्य रखना चाहिए।इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय संस्थागत जवाबदेही के दृष्टिकोण से देखा जाए। यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या गबन सिद्ध होता है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार सिद्ध होते हैं तो संबंधित संस्थाओं की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना भी उतनी ही आवश्यक होगी। कानून का शासन यही मांग करता है कि निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हो, न कि भावनाओं या राजनीतिक ध्रुवीकरण के आधार पर।

साथियों, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। विश्व के अनेक देशों में धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए कड़े ऑडिट,डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी तंत्र लागू किए जाते हैं। अयोध्या जैसे वैश्विक धार्मिक केंद्र के लिए भी पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता का प्रश्न है। यदि इस विवाद से सीख लेकर अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था विकसित की जाती है तो यह भविष्य में धार्मिक संस्थानों के सुशासन का एक आदर्श मॉडल बन सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि, 22 जून 2026 तक की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि मामला अभी जांच और न्यायिक परीक्षण के दौर में है।एसआईटी ने अपनी जांच को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है, न्यायालय में याचिका विचाराधीन है, और ट्रस्ट ने दान प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के कदम उठाए हैं।

अंतिम सत्य जांच रिपोर्ट, न्यायालय के आदेश और उपलब्ध साक्ष्यों से ही सामने आएगा। किंतु एक बात निर्विवाद है,अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और इस आस्था की रक्षा केवल भव्य निर्माण से नहीं बल्कि पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदार प्रशासन और जवाबदेह संस्थागत व्यवस्था से ही संभव है।

राशिफल

मेष राशि आज भाग्य आपके लिए रिश्तों के खजाने का ताला खोल सकता है। अपनों का साथ व सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा व्यापार में नई संभावनाएं उभरेंगी। लंबे समय से चल रही किसी चिंता से भी राहत मिलने के संकेत हैं।

वृषभ राशि वृषभ राशि वालों को धन लाभ होगा। लेकिन किसी पुराने फैसले को लेकर मन में थोड़ी कसक रह सकती है। इस समय नई संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकता है।

मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए दिन खुशियां लेकर आया है। आपके सितारे बता रहे हैं कि, आज रिश्तों में मिठास घुलने का दिन है। संतान की किसी उपलब्धि से गर्व महसूस होगा और कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सराहे जा सकते हैं। कार्यों में धीरे-धीरे सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि-कर्क राशि वालों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। मन को गहरी शांति मिलेगी। मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से भीतर खुशी और संतोष का अनुभव होगा। मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

सिंह राशि-सिंह राशि वालों को लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। विवाहित लोगों के जीवन में खुशियों के नए अवसर बन सकते हैं। आप घूमने के लिए दोस्तों के साथ जाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ी उलझनों में राहत मिल सकती है। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है।

कन्या राशि-किसी करीबी से मिली सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। विवाह से जुड़ी किसी रुकावट के दूर होने से घर में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। आज मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। इसके अलावा परिवार के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा।

तुला राशि-तुला राशि वालों को दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से बचना होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना लाभदायक रहेगा। पुराना लेन-देन सुलझ सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

वृश्चिक राशि-संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। भाई-बहनों के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है। इसके अलावा क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। परिवार का सहयोग आपका आत्मबल मजबूत करेगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं।

धनु राशि-जिस काम को पूरी लगन से करेंगे, उसमें सफलता की संभावना प्रबल रहेगी। इसके अलावा धनु राशि वालों की आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खास बात यह है कि, पुराने मित्र से मुलाकात मन को ताजगी और खुशी देगी। किसी अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा।

मकर राशि-मकर राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा, क्योंकि परिवार के लोगों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। व्यापारिक कारणों से बाहर जाने का अवसर मिल सकता है।

कुंभ राशि-कुंभ राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा, क्योंकि आज आप स्वयं को हल्का महसूस करेंगे। दिन नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दूसरों के मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचना बेहतर रहेगा।

मीन राशि-आज कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्न कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का असर साफ दिखाई देगा और सम्मान बढ़ेगा। करियर से जुड़े किसी नए अवसर पर विचार कर सकते हैं।

रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत बढ़ रही न्यायिक सुगमता

श्रीअर्जुन राम मेघवाल

न्याय सदा से ही मानव सभ्यता का एक अत्यबधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न स्तंभ रहा है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा तथा उसके स्थायी प्रतीक सामूहिक रूप से उन संस्थागत व्यवस्थातओं को दर्शाते हैं जिन्होंने मानव सभ्यूता की विकास यात्रा को सही मार्ग पर आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया और निरंतर आगे बढ़ने में सहायता की। मानव सभ्यगता के अनवरत विकास के फलस्व्रूप ज्ञान-विज्ञान और

तकनीक से समृद्ध आधुनिक समाज में एक-दूसरे से जुड़े व्य(क्तियों और समुदायों के आपसी संबंधों में भी विभिन्नम विचारों और मतों के कारण परिवर्तन आया है, तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी उन्नरति ने देश की सीमाओं से आगे जाकर विचारों के निर्बाध आदान-प्रदान को और अधिक सुगम बनाया है। अनादि काल से, एक विचार की दूसरे विचार पर श्रेष्ठता स्थाधपित करने की होड़ न्यायशास्त्र के विकास की एक मजबूत नींव रही है। युगों से विचारों और मूल्यों के इस अंतर्संघर्ष के बीच न्यायिक संस्थानों ने सत्य, निष्पक्षता और विधि के शासन में लोगों के विश्वास को पुनः स्था पित करने की जिम्मेरदारी निभाई है। इन्होंने एक सेतु का काम किया है जो प्रत्येक संबंधित पक्ष को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो स्वयं को अलग-थलग महसूस करते हैं, न्याय और सामूहिक कल्या ण की एक व्यापक प्रक्रिया से जुड़ाव, विश्वाबस और सहभागिता का अनुभव कराता है।

इसी स्थाुयी संस्थाागत प्रतिबद्धता के कारण एक ऐसी सशक्त व्यवस्था निर्मित होती है जो न केवल न्यारय तक पहुंच सुनिश्चित करती है बल्कि प्रत्येकक नागरिक के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए अनिवार्य है। वर्तमान संदर्भ में विकसित भारतीय न्याययशास्त्र ने स्व यं को आधुनिक चुनौतियों और उपलब्ध। अवसरों के अनुरूप ढाल लिया है। हमारी संवैधानिक विरासत हमें स्विंतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रप निर्माताओं का स्विप्नत साकार करते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में सतत मार्गदर्शन प्रदान करती है। संविधान की प्रस्ताकवना में निहितन्या य की त्रिवेणी अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्या्यतथास्वातंत्रता, समानता और बंधुत्वीके आदर्श संस्थाओं और व्य क्तियों दोनों के लिए एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करते हैं। स्वतंत्र भारत को संविधान के रूप में एक आदर्श मार्गदर्शक प्राप्त हुआ जिसने हमारे राष्ट्र की प्रगरति की दिशा निर्धारित की।

देश की आजादी के बाद यद्यपि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, फिर भी गहरी जड़ें जमा चुकी औपनिवेशिक मानसिकता भारतीय चिंतन और मूल्यों के लिए एक बौद्धिक अवरोध बनी रही। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, उसके बाद भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए दंडात्मक कानून तथा विभिन्नऔ नीतियों ने नियमों का एक जटिल जाल बुन दिया, जिसने देश की जनता की स्वतंत्रता को सीमित किया। 19वीं सदी की मानसिकता और 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते।

हमें अपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों पर अपार गर्व है। फिर भी, जब हम मोदी सरकार की बारह वर्षों की विकास यात्रा पर नजर डालते हैं तो शासन व्य वस्था में एक स्पष्ट और सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है जिसने नागरिकों के जीवन को अनेक स्तीरों पर प्रभावित किया है। वर्ष 2014 को हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा के एक महत्वोपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। यह वह वर्ष था जबकि देश मेंयुवाओं की विशाल आबादी (Demographic Dividend) को देश के विकास में सर्वाधिक महत्व पूर्ण (Development Dividend) मानने वाले तीव्र गति से विकसित हो रहे भारत की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया गया।

देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में संपूर्ण शासन व्य वस्थाा नेरिफॉर्म एक्स प्रेस से प्रेरित विकास की प्रक्रिया को तेजी से अपनाते हुए सशक्तिकरण की शक्ति का परिचय दिया है। इसकी यात्रा को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है कि यह जमीनी स्तर से 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देने का प्रयास है। साथ ही, 'राष्ट्र प्रथम' के दृष्टिकोण को शीर्ष स्तर से लागू करना भी इसका उद्देश्य है।

इसी प्रकार, भारत कीन्यायिक सुधारों की यात्रा भी व्यापकता, नवाचार और गहन सामाजिक एवं सभ्यतागत प्रतिबद्धता की एक प्रेरक गाथा रही है।यह एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें विधायी आधुनिकीकरण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और डिजिटल नवाचार शामिल हैं।

'ईज ऑफ जस्टिस' हमारे लिए मात्र एक कथन नहीं है बल्कि यह एक सुधार का मंत्र है जिसमें न्यासय के लिए अदालत की शरण में जाने वालों के लिए 'ईज ऑफ इंगेजमेंट', अधिवक्ता्ओं और न्यादयाधिशों के लिए 'ईज ऑफ वर्किंग' तथा नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ अंडरस्टैंयडिंग' शाामिल है।

न्यासय हेतु अदालतों की शरण में जाने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए DISHA योजना के तहत टेली-लॉ, न्यामय बंधु और प्रो बोनो सेवाओं के विस्ताSr ने न्योय प्राप्ति को अत्यंमत सुलभ और किफायती बना दिया है। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संचालित टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के 112 लाख से अधिक लाभार्थियों को अदालतों में मुकदमे दायर करने से पहले मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्तम करने का लाभ मिला है। ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्र की सेवाओं ने अदालत में मुकदमा दायर करने वाले व्यैक्तियों और न्यायिक व्यवस्थान के बीच नियमित संवाद एवं संपर्क को और अधिक सरल बनाया है। आधुनिक प्रौद्यो(गिकी और सामुदायिक सहभागिता के समन्वीय का भारत का यह अनूठा मॉडल वैश्विक स्तोर पर एक मानक के रूप में उभरा है।

अधिवक्तायओं और न्याययाधीशों के लिए 'ईज ऑफ वर्किंग' को डिजिटल और भौतिक अवसंरचना दोनों में व्यौपक विस्ताकर द्वारा उल्ले खनीय रूप से सुदृढ़ किया गया है। चूंकि जिला एवं अधीनस्थे न्यापयपालिका देश के अधिकांश नागरिकों के लिए न्या यिक व्य वस्थाल का पहला संपर्क बिंदु है, अतः इसे सुदृढ़ करना एक अनिवार्य और व्याुवहारिक प्राथमिकता बनी हुई है। इसी दृष्टि से, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत न्यावयालय भवन, अधिवक्ताब कक्षों, आवासीय इकाइयों तथा डिजिटल अवसंरचना के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, देश में न्यायालय भवनों की संख्या वर्ष 2014 के 15,818 से बढ़कर 22,712 हो गई है तथा अत्या धुनिक एकीकृत न्याायालय परिसरों के विकास हेतु वर्ष 2014 के बाद से अब तक 9,400.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्तस, 7200 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्य0य से शुरू की गई ई-कोर्ट चरण-III परियोजना का उद्देश्य न्याकयालयों को पूर्णतः डिजिटल, पेपरलेस और एआई-सक्षम न्या य वितरण संस्थोनों में परिवर्तित करना है। विडियो कॉन्फ्रें सिंग सुविधाएं, वर्चुअल कोर्ट और अदालती कार्यवाही की लाईव स्ट्री मिंग जैसी पहलों ने न्या यपालिका को लोगों के और करीब ला दिया है तथा न्या य वितरण को अधिक सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाया है।

भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग' का होना 'ईज ऑफ जस्टिस' के व्याापक ढांचे का एक अत्यंत महत्वजपूर्ण स्ंभि है। इस उद्देश्यह को ध्याईन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS) और भाषिणी (Bhashini) जैसे एआई- संचालित ने(चुरल लैंग्वे ज प्रोसेसिंग उपकरण उच्चैतम न्याोयालय के निर्णयों एवं आदेशों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं, जिससे आम जनता के लिए कानूनी जानकारी अधिक सुलभ हो रही है। इस प्रयास को और अधिक सशक्तं बनाने के लिए राष्ट्रीाय न्याोयिक डेटा ग्रि(ड (NJDG) जो एक सांख्यिकीय एवं विश्ले षणात्म(क मंच है, 340 मिलियन से अधिक अदालती आदेशों एवं उनसे सं(बंधित जानकारियों के विशलेषण तक एक क्लिक में पहुंच प्रदान करता है। साथ ही, सरकार शिक्षाविदों के सहयोग से सरल और सहज विधायी प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) को बढ़ावा दे रही है ताकि कानूनों को अधिक सरल और आम नागरिकों के अनुकूल बनाया जा सके।

भारत में औपनिवेशिक दंड संहिता के स्थागन पर नई आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने से दाण्डिक व्यदवस्था् के स्थारन पर न्या यिक व्यधवस्थां स्था पित हुई है। ई-कोर्ट, ई-प्रोसीक्यूणशन, ई-प्रिजन और ई-फोरेंसिक को अपराध तथा आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) के साथ जोड़ना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम है।

'न्याय श्रुति' प्लेटफॉर्म ने वर्चुअल उपस्थिति और गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को इतनी कुशलता से सुगम बनाया है कि जब कोई अदालत किसी नागरिक को जमानत देती है, तो डिजिटल जमानत आदेश तुरंत जेल पोर्टल पर पहुंच जाता है जिससे कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक देरी समाप्त हो जाती है, जो पारंपरिक रूप से समय पर रिहाई में बाधा डालती थी। यह वास्तविक समय में केस डेटा के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है और एक अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) का मार्ग प्रशस्त करता है।

उच्च न्यायपालिका की आवश्यकताओं को ध्याान में रखते हुए भी सार्थक उपाय किए गए हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2014 के 906 से बढ़कर 1122 हो गई है। उच्चातम न्यायालय में न्या्याधीशों की संख्या4 भी 31 थी जिसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 34 कर दिया गया है तथा उच्चंतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से इसे बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। पिछले 12 वर्षों में देश के उच्च न्यायालयों में सामाजिक रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले 1175 न्यायाधीशों की तथा उच्चेतम न्यायालय में 77 न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्यपालिका और न्याजयपालिका के समन्वित प्रयासों को दर्शाती है।

यह स्पष्ट है कि अनावश्यक कानूनों की जटिलता संबंधित पक्षों पर अनावश्य क बोझ डालती है।40,000 से अधिक अनावश्यलक अनुपालनों (Compliances) को समाप्तर करने तथा औपनिवेशिक युग के 1725 निरर्थक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने सेविभिन्न क्षेत्रों में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में उल्ले खनीय सुधार हुआ है। साथ ही, आर्बिट्रेशन संबंधी कानूनों को सुदृढ़ करना, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जैसी संस्थाभओं की स्थासपना तथा मेडिएशन एक्टु 2023 के माध्येम से वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है।

वर्तमान में जबकि विश्व जटिल भू-राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, भारत के विधिक और राजनयिक नेतृत्वन नेBRICS देशों के न्याोयमंत्रियों की बैठक, 2026के दौरान मेडिएशन और आर्बिट्रेशन को विवाद समाधान के लिए अधिक प्रभावी और सुलभ माध्य6म के रूप में स्थारपित करने हेतु एक सामूहिक प्रतिबद्धता के रूप मेंगांधीनगर घोषणा पत्रको अपनाने में महत्वरपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐसे वैश्विक सहयोगों का उद्देश्यग न्या यालयों में लंबित मामलों की संख्याार को कम करना, व्याोपार और निवेश के लिए स्थिर एवं सुविचारित परिवेश को सृजित करने पर अत्याधिक बल देना तथा अनावश्याक मुकदमेबाजी से बचना है।

ये सभी पहलें एक साझा दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि न्याय प्राप्तस करने की इच्छार रखने वाले प्रत्येसक व्यहक्ति को एक जवाबदेह, सुलभ और सहयोगी शासन व्यतवस्था प्राप्त हो। जैसे-जैसे हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत @2047 की यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, हम एक ऐसे भावी न्यालय प्रणाली के निर्माण के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं जो लचीली, नवोन्मेसषी, समावेशी और 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षाओं से प्रेरित हो।

(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं)

एक नजर

श्रमिकों के बच्चों को उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों में मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

बीजापुर 23 जून। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। योजना के लिए 22 जून से 3 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की प्रथम दो संतानों का चयन किया जाएगा, जिनका श्रमिक पंजीयन कम से कम एक वर्ष पुराना हो तथा जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश ले रहे हों। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक प्रदेश के उत्कृष्ट आवासीय विद्यालयों में पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ निर्माण कार्य से जुड़े लगभग 60 श्रेणियों के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मिलेगा। इनमें राजमिस्त्री, रेजा-कुली, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कारपेंटर, मिस्त्री, हेल्पर, टाइल्स मिस्त्री, स्टील फिक्सर, फॉर्म वर्कर सहित अन्य निर्माण कर्मी शामिल हैं। श्रम निरीक्षक बीजापुर सोपान कर्णेवार ने बताया कि अभिभावक Shramev Jayate पोर्टल, Shramev Jayate मोबाइल ऐप, नजदीकी श्रम संसाधन केंद्र, चॉइस सेंटर अथवा जिला श्रम कार्यालय बीजापुर के कक्ष क्रमांक-6 में जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने श्रमिक परिवारों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य का अवसर मिल सके।

बस्तर में स्वच्छता के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर गांवों में अभियान जारी

जगदलपुर, 23 जून। (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। बस्तर जिले को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। पूरे देश में 01 अप्रैल 2026 से लागू हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बस्तर जिले की ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गति देने के लिए ग्राम पंचायत आड़ावाल, चेराकुर, बुरुन्दवाड़ा, बिलोरी और हल्बा कचोरा सहित कई गांवों में जन-जागरूकता चरम पर है, जहां ग्राम पंचायत भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और हाट-बाजारों में दीवार लेखन और ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। दीवारों पर चार डिब्बा चार रंग, स्वच्छता का नया उमंग और हरा, नीला, लाल और काला (या पीला), यही है स्वच्छता का उजाला जैसे आकर्षक नारे लिखे गए हैं जो ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। इस नई पहल के तहत ग्रामीणों को अपने घरों से ही कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर डस्टबिन में डालने की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसके तहत रसोई के कचरे, फल, सब्जी के छिलके और बासी भोजन जैसे गीले कचरे को हरे डस्टबिन में डालने की सलाह दी गई है। वहीं कागज, प्लास्टिक, गत्ता, कांच और बोतल जैसे सूखे कचरे के लिए नीले डस्टबिन का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। सैनिटरी पैड, डायपर, मेडिकल वेस्ट और ब्लेड जैसे सैनिटरी अपशिष्ट को लाल डस्टबिन में तथा खराब बल्ब, ट्यूबलाइट, मोबाइल और चार्जर जैसे हानिकारक ई-वेस्ट को पीले डस्टबिन में पृथक रूप से संग्रहित करने की समझाइश दी जा रही है। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए स्वच्छता दीदियां, महिला स्व-सहायता समूह और पंचायत प्रतिनिधि खुद घर-घर पहुंचकर लोगों को कचरा अलग करने की इस पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा रहे हैं। इस जागरूकता अभियान के साथ-साथ अब हर घर, दुकान, होटल, स्कूल और बाजार से नियमित रूप से कचरा संग्रहण किया जाएगा और इसके बदले स्वच्छता शुल्क का नियमित संग्रह होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों या सूखे स्थानों पर कचरा फेंकने या जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने पर तत्काल जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसी मुहिम के तहत जिले की बुरुन्दवाड़ा और बिलोरी पंचायतों ने एक बड़ी मिसाल पेश की है।

इंद्रावती प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शरद अवस्थी ने किया पदभार ग्रहण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 23 जून । इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष बस्तर से भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद अवस्थी ने आज सोमवार को एक गरिमामय समारोह में पदभार ग्रहण किया। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर के अलावा सुकमा,दंतेवाड़ा समेत अन्य जिलों से भी भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। पद का दायित्व लेने के बाद शरद अवस्थी ने कहा कि इंद्रावती नदी हमारी जीवनदायनी है। किसानों से लेकर आम लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इसके लिए शासन ने काफी बड़ी योजनाएं बनाई है। वर्तमान में इंद्रावती के उन्नयन के लिए 2000 करोड रुपए से ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हैं । उन्होने कहा कि शासन द्वारा जो उन्हें दायित्व दिया गया है सभी के सुझाव के

साथ हर संभव प्रयास करते हुए उसका निर्वहन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने विभाग के अफसर को भी कहा कि आपसी समन्वय से सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि शरद चाचा को राजनीति में काम करते बचपन से देखा है। उनके नेतृत्व में प्राधिकरण में ज्यादा से ज्यादा सुविधा बढ़ेगी। बस्तर का उल्लेख करते मंत्री ने कहा पहले नक्सलवाद के कारण कुछ दिक्कतें थीं लेकिन प्रधानमंत्री ने देश को नक्सल मुक्त करवा दिया है। यहां सबसे ज्यादा काम किसानों, सिंचाई के क्षेत्र में हो सकते हैं। कभी इरिगेशन का बजट 2200 करोड़ रूपया होता था। अब 4000 करोड रुपए के काम चल रहे हैं। प्रदेश सरकार सिंचाई की सुविधाओं को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। इंद्रावती का 310 टीएमसी जल भद्रकाली में गोदावरी नदी से मिल जाता है। उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। अब इसका उपयोग होगा तो सिंचाई में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक किरण देव ने कहा शरद अवस्थी हम सबके लिए बहुत सम्माननीय हैं। इस मंच पर जितने भी नेतागण बैठे हैं सभी ने उनसे कुछ सीख कर साथ काम किया है। इनकी खासियत है कि जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करते हैं। बस्तर जिला मुख्यालय के पास ही देउर गांव और मटनार में बैराज स्वीकृत हुए हैं, आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप,पूर्व सांसद एवं सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप के अलावा वेदवती कश्यप, रूप सिंह मंडावी, महापौर संजय पांडे, लच्छु राम कश्यप, डॉक्टर सुभाई राम कश्यप, संतोष बाफ्ना, वेद प्रकाश पांडे, विनायक गोयल समेत अन्य वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तुलिका कर्मा ने पंचायतों में सीएसआर मद से कराए जा रहे विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया पर उठाए सवाल

- जिला पंचायत सदस्य तुलिका ने पत्रवार्ता में सांसद-विधायक पर भी लगाए गंभीर आरोप
- स्थानीय ठेकेदारों की अनदेखी कर बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा 23 जून। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने आज पत्रवार्ता लेकर एनएमडीसी द्वारा किरंदुल-बचेली क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सीएसआर मद से कराए जा रहे विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे पारदर्शिता और नियमों के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के स्थानीय एवं पंजीकृत ठेकेदारों की अनदेखी कर बाहरी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शासन की मंशा और विकास कार्यों की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही हैं।

तुलिका कर्मा ने कहा कि एनएमडीसी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों की निविदा प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये के कार्यों को सीमित निविदा के माध्यम से केवल कुछ ठेकेदारों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि एनएमडीसी के नियमों के अनुसार निर्धारित 2 लाख की राशि से अधिक के कार्यों के लिए खुली ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि स्थानीय पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों को जानकारी तक नहीं दी गई, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। निविदा राशि टेंडर वेबसाइट में नहीं दर्शाया गया और निविदा इस तरह से लॉक की गई थी कि वह खुल ही नहीं रही थी साथ ही कुछ दिनों तक तो टेंडर एनएमडीसी के साइट पर प्रकाशित भी नहीं किया गया था। तुलिका कर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे लोगों को भी निविदा प्रक्रिया में शामिल किया गया है जिनका क्षेत्र में पूर्व कार्य अनुभव नहीं है और न ही वे स्थानीय स्तर पर पंजीकृत हैं।

जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि यदि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है तो सभी कार्यों की खुली एवं निष्पक्ष निविदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 20 से 40 करोड़ के कार्य कराए जा रहे हैं। सार्वजनिक धन का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए, न कि किसी विशेष समूह को लाभ पहुंचाने के लिए। पत्रवार्ता के दौरान तुलिका ने कहा कि विधायक चैतराम अटामी भ्रष्टाचार को देखकर भी अनदेखा कर कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री, विधायक और सांसद सभी मिलकर लगातार बाहरी ठेकेदारों को जिले में कार्य दिला रहे हैं साथ है और मोटी रकम कमीशन के तौर पर ले भी रहे हैं।

तुलिका कर्मा ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और एनएमडीसी प्रबंधन से मांग की है कि पूरी निविदा प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और लाभान्वित पक्षों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा की जनता विकास चाहती है, लेकिन विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और बंद कमरे में फैसले किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ठेकेदारों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के लोगों के अधिकारों और विकास कार्यों में पारदर्शिता की रक्षा की जा सके। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर किरंदुल कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी एनएमडीसी प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेन्द्र गुप्ता, महिला शहर अध्यक्ष इंदिरा शर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा, मनोज कौरव, सत्यभान सिंह जादौन, रविश सुराना, जीतू कश्यप उपस्थित थे।

दंतेवाड़ा में आदिवासी संगठनों की विशाल रैली, धर्म कोड व पेसा लागू करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 23 जून। आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और स्वशासन की मांग को लेकर रविवार को दंतेवाड़ा में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले लोगों ने रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को ज्ञापन भेजा। दंतेवाड़ा के दुर्गा मंडप में जमा होकर रैली के माध्यम से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने पेसा कानून लागू करो, आदिवासी धर्म कोड जोड़ो, जल-जंगल-जमीन हमारा है के नारे लगाए।

ज्ञापन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ का 61वा हिस्सा पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आता है, फिर भी संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा। प्रमुख मांगों में जनगणना में पृथक आदिवासी धर्म कोड जोड़ना, पेसा नियम 2022 का पूर्ण क्रियान्वयन, बस्तर-सरगुजा में इनर लाइन परमिट लागू करना, भ्रष्ट को सक्रिय करना और छात्रवृत्ति में आय सीमा की बाध्यता खत्म करना शामिल है। सर्व आदिवासी समाज दंतेवाड़ा के अध्यक्ष सुरेश कर्मा ने कहा हमारी संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश चल रही है। धर्म कोड हमारा हक है। सरकार ने नहीं सुना तो उग्र आंदोलन होगा। रैली में कोया समाज अध्यक्ष बल्लू भवानी, सुरजीत सेठिया कलर समाज अध्यक्ष ,धीरज राणा अध्यक्ष हल्बा समाज, सोमारू कड़ती जिला पंचायत सदस्य ,आशा राम कर्मा उप अध्यक्ष भीम आर्मी ,संतु राम कश्यप पूर्व सरपंच बालूद ,आदि समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। ज्ञापन का आधार 6 जून को रायपुर के वृंदावन हाल में हुई संयुक्त बैठक में पारित प्रस्ताव है। संगठनों ने 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर चक्काजाम की चेतावनी दी है।

आदिवासी अधिकारों की रक्षा को लेकर सर्व समाज लामबंद, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

बीजापुर 23 जून। जिला मुख्यालय में आदिवासी समाज द्वारा सोमवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, युवा एवं जनसंगठनों के प्रतिनिधियों तथा सर्व समाज प्रमुखों ने आदिवासी समाज के संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के हितों की रक्षा हेतु लामबंद हुए। ज्ञापन के अनुसार रायपुर के वृंदावन हॉल में आयोजित संयुक्त बैठक में पारित प्रस्तावों के आधार पर यह मांगपत्र तैयार किया गया है। प्रदेश के लगभग 61 प्रतिशत भूभाग पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। ऐसे में संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जनगणना में पृथक आदिवासी धर्म कोड की मान्यता, परिसीमन के दौरान आदिवासी प्रतिनिधित्व की सुरक्षा, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, निजीकरण पर रोक तथा जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की

गई। साथ ही आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों की जांच, भू-माफिया नियंत्रण कानून लागू करने, भूमि अधिग्रहण एवं खनन परियोजनाओं में ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति तथा खनिज संपदा से होने वाले लाभ में स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। इसके अलावा नक्सल मामलों में जेलों में बंद निर्दोष आदिवासी युवाओं की रिहाई का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया।

ज्ञापन में धर्म परिवर्तन के आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा समाप्त करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए देवगुड़ियों, सरना स्थलों, गोटुल और अन्य पारंपरिक आस्था केंद्रों को कानूनी संरक्षण देने, पेसा कानून एवं वन अधिकार मान्यता अधिनियम (एफआरए) के पूर्ण क्रियान्वयन तथा आदिवासी शिक्षा और मातृभाषा संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाने की मांग भी शामिल है। सर्व समाज ने राज्यपाल से आदिवासी समाज की अस्मिता, स्वशासन, परंपरागत अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक हस्तक्षेप कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी, कंवर समाज अध्यक्ष कमलेश पैंकरा, गोंड समाज अध्यक्ष पांडुराम तेलाम, मुरिया समाज के पाकलु तेलम, उरांव समाज अध्यक्ष पीआर भगत, तेलगा समाज प्रमुख मंगल रोटेल, महिला प्रभाग की सावित्री हपका, रानी पुनेम, सरोजना ताती, रैनू ओयाम, गुड्डू मोडीयम सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं समाज प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वार्ड क्रमांक-13 में खुले बोर के गड्ढे से हादसे की आशंका

कांकेर, 23 जून। जिले के भानुप्रतापपुर नगर के वार्ड क्रमांक 13 में सड़क पर किए गए बोर खनन का मामला अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। विवाद के बाद प्रशासन ने बोर खनन का कार्य तो रुकवा दिया, लेकिन मौके पर बने गहरे गड्ढे और खुले बोर को अब तक सुरक्षित तरीके से बंद नहीं कराया गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने यह सवाल लगातार उठ रहे हैं कि यदि इस खुले बोर में कोई बच्चा या राहगीर गिरकर हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? स्थानीय निवासी अभिषेक सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने इस मामले में कई बार प्रशासन को लिखित शिकायत देकर खुले बोर को तत्काल बंद कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि संबंधित व्यक्ति हरीश शर्मा द्वारा सड़क क्षेत्र में बोर खनन कराया गया था।

फर्जी शिकायतों और कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने दी अदालत जाने की चेतावनी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 23 जून। शान द्वारा मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन की बस्तर जिला अध्यक्ष रीमा दानी ने आरोप लगाया है कि तथाकथित छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारियों द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से कर्मचारियों में भय और असंतोष का माहौल बन रहा है तथा शासकीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। रीमा दानी ने जारी बयान में कहा कि संबंधित संगठन को शासन स्तर पर कर्मचारियों के पक्ष में पत्राचार करने की अनुमति नहीं है, इसके बावजूद संगठन के पदाधिकारी विभागीय मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के विरुद्ध निराधार शिकायतें, ब्लैकमेलिंग, धमकी और शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने जैसी गतिविधियां लगातार की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि विवादित संगठन के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई थी, जिस पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन जांच प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर उक्त संगठन द्वारा की जा रही शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने से कर्मचारियों में नाराजगी है।

रीमा दानी का कहना है कि संगठन के गठन के लगभग छह माह बाद भी कर्मचारियों के हित में कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है, जबकि कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर संगठन को संचालित कर रहे हैं और कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतों और मानसिक उत्पीड़न का सिलसिला नहीं रुका, तो संगठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेगा। साथ ही शासन और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

शासकीय आवास आवंटन में गंभीर अनियमितता: नोडल अधिकारी डॉ. सरिता थॉमस पर नियमों के उल्लंघन के आरोप

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता/ मृण्मय बारोई

जगदलपुर, 23 जून। महारानी अस्पताल जगदलपुर में पदस्थ नोडल अधिकारी डॉ. सरिता थॉमस एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में आ गई हैं। उपलब्ध पुख्ता दस्तावेजों और साक्ष्यों के अनुसार, उन पर शासकीय आवास आवंटन नियमों को ताक पर रखकर सरकारी आवास हासिल करने के आरोप लगे हैं।

शपथपत्र में जानकारी छुपाने का आरोप, शहर के पॉश इलाकों में हैं निजी फ्लैट्स: प्राप्त पुख्ता जानकारी के अनुसार, डॉ. सरिता थॉमस के नाम पर जगदलपुर शहर के महंगे और पॉश इलाकों में निजी आवासीय संपत्तियां मौजूद हैं। इसके बावजूद उन्हें शासकीय आवास आवंटित किया गया है। बताया जा रहा है कि आवास आवंटन के लिए प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में उन्होंने स्वयं, पति और सास-ससुर के नाम पर किसी भी प्रकार का मकान न होने का दावा किया था, जो वास्तविक स्थिति से पूरी तरह भिन्न है।

पुख्ता साक्ष्यों के मुताबिक, शहर के पॉश वर्गीज कॉलोनी स्थित विशाल मेगा

मार्ट के ऊपर डॉ. थॉमस के नाम पर एक 2-BHK फ्लैट दर्ज है। खरीदारी के वक्त इसकी अनुमानित कीमत करीब 38 से 40 लाख रुपये थी, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है। इसके अतिरिक्त, लालबाग हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भी उनके नाम पर एक अन्य फ्लैट होने की जानकारी सामने आई है। ये दोनों निजी आवास वर्तमान में किराए पर चल रहे हैं। वहीं, धरमपुरा क्षेत्र में उनके ससुराल पक्ष का पारिवारिक मकान भी मौजूद है।

पात्र कर्मचारी वंचित, नियमों की अनदेखी से रोष: इस मामले में पूर्व में भी शिकायतें की जा चुकी हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 'छत्तीसगढ़ शासकीय आवास आवंटन नियम 2000' के तहत यदि किसी शासकीय कर्मचारी, उनके पति/पत्नी या आश्रित परिवार के नाम पर कार्यस्थल से निर्धारित दूरी के भीतर निजी मकान उपलब्ध हो, तो वे शासकीय आवास के पात्र नहीं होते। ऐसे में इस आवंटन प्रक्रिया और शपथपत्र की सत्यता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। महारानी अस्पताल के कई अधिकारी और कर्मचारी, जो नियमानुसार आवास के वास्तविक हकदार हैं, वे आज भी इस सुविधा से वंचित हैं। कर्मियों का आरोप है कि अपात्रों को अनुचित लाभ मिलने के कारण जरूरतमंदों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

सिविल सर्जन का मिथ्या आचरण; दस्तावेजों से खुली पोल: मामले की पड़ताल के लिए जब तत्कालीन एवं वर्तमान सिविल सर्जन डॉ. संजय प्रसाद से फोन पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने पहले तो टीएल बैठक का हवाला देकर मामले को टालने का प्रयास किया। जब संवाददाता ने संक्षिप्त जवाब का आग्रह किया, तो उन्होंने दावा किया कि डॉ. सरिता थॉमस को आवास सीएमएचओ कार्यालय द्वारा आवंटित किया गया है।

दस्तावेज में सच आया सामने

सिविल सर्जन का यह बयान पूरी तरह निराधार और तथ्यों को छुपाने वाला साबित हुआ है। कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, जगदलपुर (बस्तर)* के आदेश पत्र क्र./सी.एस./स्था./2021/2716, दिनांक 22/10/2021 के अनुसार, तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा ही 'छत्तीसगढ़ शासकीय आवास आवंटन नियम 2000' के तहत डॉ. सरिता निर्मल (थॉमस), चिकित्सा अधिकारी के नाम पर सी-4 शासकीय भवन आवंटित किया गया था। इस विरोधाभासी और मिथ्या आचरण ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

निष्पक्ष जांच और कोर्ट जाने की तैयारी

ठोस साक्ष्यों के सार्वजनिक होने के बाद अब गेंद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पाले में है। मामले में नियमों के तहत तत्काल आवास निरस्तीकरण, बेदखली और कड़ी विभागीय कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष ले जाएंगे और न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

दंतेवाड़ा जिले तक मानसून के पंहुचने की आधिकारिक पुष्टि

जगदलपुर, 23 जून। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले तक मानसून के पंहुचने की आधिकारिक पुष्टि आज सओमवार को कर दी है। बस्तर संभाग में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आधिकारिक तौर पर 22 जून को दस्तक देने की बात कही है। इसका असर पूरे बस्तर संभाग में आज सुबह से ही अच्छी बारिश के साथ देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बस्तर में मानसून के प्रवेश साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। इस दौरान बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। दरअसल, जून के बीते 22 दिनों में राज्य में केवल 32.3 मिमी. बारिश हुई है, और किसी भी जिले में सामान्य वर्षा का कोटा पूरा नहीं हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों को मानें तो जून के महीने में अक्सर कम वर्षा का संकट सामने आता है।

एक नजर

भूतपूर्व सैनिकों ने विश्व योग दिवस पर योगाभ्यास कर दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

रायगढ़, 23 जून। विश्व योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा रायगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के साथ सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के पूर्व सैनिक, उनके परिजन तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। योगाभ्यास के पश्चात जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं कमाण्डर हरिश्चन्द्र तिवारी ने उपस्थित लोगों को योग के इतिहास, महत्व और दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और संतुलित जीवन जीने की कला है। उन्होंने कर्म योग, ध्यान योग और प्राणायाम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन में योगी बनकर समाज के लिए उपयोगी बनने का संदेश दिया। विश्व योग दिवस के अवसर पर आमजन एवं युवाओं में योग के प्रति जागरूकता फैलाने तथा इसके महत्व का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से कमला नेहरू पार्क स्थित योग स्थल से कारगिल चौक स्थित शौर्य स्थल तक पैदल एवं बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में शामिल भूतपूर्व सैनिकों, युवाओं और नागरिकों ने नियमित योग अपनाने तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया। विश्व योग दिवस के इस आयोजन ने स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की भावना को एक साथ जोड़ते हुए लोगों को योग के प्रति प्रेरित किया।

प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और गंभीरता से करें कार्रवाई : कलेक्टर

रायगढ़, 23 जून। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज जिला कलेक्टोरेट परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रस्तुत कीं। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।जनदर्शन के दौरान ग्राम लोधिया की श्रीमती सीता जायसवाल ने पात्रतानुसार शौचालय निर्माण एवं उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ दिलाने की मांग की। ग्राम रेगड़ी के श्री बहादुल ने वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने पूर्वजों द्वारा उपयोग की जा रही वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम सकरलिया के श्री शनि राम बिरहोर ने भूमि के नक्शा दुरुस्तीकरण, ग्राम करौवाडीह के ग्रामीणों ने गांव में संचालित नल-जल योजना का कार्य अधूरा होने से उत्पन्न पेयजल समस्याओं से अवगत कराते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराने, मिद्धुमुड़ा की श्रीमती गीता बाई ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत पात्रतानुसार लाभ दिलाने की मांग की।

योग दिवस पर अमृत सरोवर स्थलों पर ग्रामीणों ने किया सामूहिक योग

रायगढ़, 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न अमृत सरोवर स्थलों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन उत्साह एवं उल्लास के साथ किया गया। जिसमें ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और नियमित योग अपनाने का संकल्प लिया।जनपद पंचायत पूसौर के ग्राम पंचायत तेलीपाली स्थित अमृत सरोवर जामपाली में आयोजित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। उन्होंने सामूहिक रूप से योगासन और प्राणायाम कर योग के महत्व को समझा तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। इसी प्रकार जनपद पंचायत खरसिया के ग्राम पंचायत छोटे मुडपार स्थित अमृत सरोवर नया तालाब में भी लोगों ने भाग लिया।कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षकों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने योग को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।

लॉ एण्ड आर्डर पर बैठक 24 जून को

रायगढ़, 23 जून। कानून व्यवस्था के संबंध में 24 जून को प्रातः 10 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में औद्योगिक सुरक्षा संबंधी मॉनिटरिंग, दुर्घटना की स्थिति में तैयारी एवं तहसील स्तरीय गठित समिति की रिपोर्ट की समीक्षा, नशा मुक्ति अभियान की प्रगति, अवैध उत्खनन के प्रकरण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की कार्ययोजना एवं ब्लैक स्पॉट की जानकारी एवं सुधारात्मक कार्यों की समीक्षा तथा एजेण्डा अनुसार अन्य विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए जिले से 17 श्रद्धालु हुए रवाना, वित मंत्री ओ.पी. चौधरी ने दी शुभकामनाएं

रायगढ़, 23 जून। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के उद्देश्य से संचालित तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आज रायगढ़ जिले के 17 यात्रियों को सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी. चौधरी ने सभी यात्रियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठजनों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर उपलब्ध करा रही है।

नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का वित्त मंत्री ने किया निरीक्षण

प्रदेश का सबसे मॉडल शहर बनेगा रायगढ़ : ओपी चौधरी

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 23 जून। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने सोमवार सुबह नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के बहुप्रतीक्षित मरीन ड्राइव, नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड (आईएसबीटी), एफसीआई ऑक्सीजोन, मिद्धुमुड़ा तालाब, किसान राइस मिल ऑक्सीजोन और कयाघाट पुल सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थल पर पहुंचकर अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को सभी कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर निगम महापौर श्री जीवर्धन चौहान, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए कहा कि रायगढ़ को प्रदेश के सबसे आधुनिक, व्यवस्थित और सुविधासंपन्न शहरों में शामिल करना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि सड़क, परिवहन, पर्यावरण, जल संरक्षण और शहरी सुविधाओं से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद रायगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और प्रदेश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में उभरेगा।वित्त मंत्री ने प्रगति नगर स्थित निर्माणाधीन मरीन ड्राइव का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने समय पर मुख्य बॉक्स कल्वर्ट और डायवर्सन निर्माण कार्य पूरा होने पर संतोष व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मरीन ड्राइव केवल एक सड़क परियोजना नहीं बल्कि रायगढ़ की नई पहचान बनने जा रही है। इससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नागरिकों को एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल भी मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी नवंबर माह तक परियोजना को हर हाल में पूर्ण किया जाए ताकि शहरवासियों को जल्द इसका लाभ मिल सके।

आबकारी अमले ने 35.600 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 23 जून। जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 35.600 लीटर महुआ शराब जब्त की है। कलेक्टर के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत घरघोड़ा और खरसिया क्षेत्र में दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

सहायक आयुक्त आबकारी ने बताया कि आबकारी वृत्त घरघोड़ा की टीम ने महलोई गांव में दबिश देकर तुलसा अगरिया के कब्जे से 16.400 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की। वहीं दूसरी कार्रवाई में नवापारा वार्ड क्रमांक 08 निवासी राखी बाई पैकरा के घर से 9 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब बरामद की गई। इसी तरह आबकारी वृत्त खरसिया की टीम ने बरगढ़ गांव में कार्रवाई करते हुए प्रताप कुमार उरांव के कब्जे से 10.200 लीटर महुआ शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने बताया कि तीनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कराया गया। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुलाकात

राजा साहेब निर्वेंद्र सिंह टेकाम व गोंड समाज जिला अध्यक्ष प्रेमलाल ने सीएम साय से मुलाकात की

दल्ली राजहरा, 23 जून। लोहारा विधानसभा क्षेत्र के राजा साहब लाल निर्वेंद्र सिंह टेकाम जी व गोंड समाज के प्रमुख जिला अध्यक्ष प्रेम लाल कुंजाम के नेतृत्व मुख्यमंत्री निज निवास में विष्णु देव साय से भेट मुलाकात कर आगमी लोहारा में होने वाले विशाल जिला स्तरीय वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान समारोह व मूर्ति अनावरण में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया व समाज से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों व मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों की सौगात व समाजिक मांगों को पूरा करने का आश्वासन समाज को। दिया गया और आमंत्रण स्वीकार कर लोहारा आगमन को लेकर समाज को व क्षेत्र के लोगों आश्वस्त किया भेट मुलाकात में जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज तुका राम कोर्राम कृष्णा ठाकुर अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा जिला बालोद , थान सिंह मंडावी ग्राम पटेल टुएगोंदी ज्ञानेश्वर प्रसाद भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंडल डौंडी ,थानेश्वर यादव नगर विकास किसान समिति सदस्य लोहारा, नागेश्वर सलाम अनुसूचित जनजाति मीडिया प्रभारी मुख्य रूप से समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित ।

पुलिस ने स्कूल में विद्यार्थियों,शिक्षकों को नए कानून,साइबर अपराध,महिला बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दी

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

छुरा, 23 जून। युवाओं और विद्यार्थियों को कानूनों की जानकारी तथा साइबर अपराधों के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से थाना छुरा द्वारा सोमवार 22 जून 2026 को ग्राम पंचायत दुल्ला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ को नवीन भारतीय कानूनों, साइबर अपराधों, महिला एवं बाल संरक्षण तथा नशामुक्ति के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक ज्ञानेश्वर सिंह गंगवाल ने कहा कि बदलते समय के साथ कानूनों और तकनीक की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को नवीन भारतीय कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के बारे में सरल भाषा में जानकारी देते हुए बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।

एक क्लिक की गलती पड़ सकती है भारी- साइबर ठगी से बचने किया जागरूक

थाना प्रभारी श्री गंगवाल ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया के जरिए होने वाली धोखाधड़ी, ओटीपी साझा करने से होने वाले नुकसान तथा बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। उन्होंने किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।

महिला सुरक्षा और नशामुक्त समाज के लिए किया प्रेरित

कार्यक्रम में महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति भी जागरूक किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा अथवा अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए। साथ ही युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

'समाधान' और 'अभिव्यक्ति' एप की दी जानकारी, मौके पर कराया डाउनलोड

कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ पुलिस के ÷समाधान÷ और ÷अभिव्यक्ति÷ मोबाइल एप की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई तथा उनके मोबाइल फोन में एप डाउनलोड कराकर पुलिस सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर सिंह गंगवाल ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर ऐसे जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों में कानून, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने थाना छुरा की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में कानून के प्रति समझ विकसित करने के साथ-साथ उन्हें साइबर अपराधों और सामाजिक बुराइयों से सुरक्षित रहने के प्रति अधिक जागरूक बनाएंगे।

पीएम गति शक्ति पोर्टल से विकास परियोजनाओं में आएगी गति और पारदर्शिता: कलेक्टर

रायगढ़, 23 जून। जिला गति शक्ति समिति की द्वितीय बैठक के अंतर्गत आज कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को पीएम गति शक्ति पोर्टल की कार्यप्रणाली, उपयोगिता एवं विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इसकी भूमिका से अवगत कराना था। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिजीत बबन पठारे, सहायक कलेक्टर श्री आर. गोकुल, एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर श्री रवि राही, अपर कलेक्टर डॉ.प्रियंका वर्मा, उद्योग विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती अंजू नायक, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 23 जून। अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति एवं प्रधानमंत्री नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने की। बैठक में अल्प संख्यक समुदाय के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन, शत-प्रतिशत लाभ वितरण तथा व्यापक जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए समुदाय स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने लाभार्थियों की अद्यतन सूची तैयार कर योजनाओं की सतत निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक स्वीकृत आवासों की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण, आंकड़ों के सत्यापन तथा पात्र परिवारों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सहकारिता, कृषि, मत्स्य पालन, रेशम, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा रोजगार विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान छात्रवृत्ति, सरस्वती साइकिल योजना, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आत्मा योजना, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार पंजीयन एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, विशेष जागरूकता शिविरों के आयोजन तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। उद्योग विभाग को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) सहित उद्यमिता एवं स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।

किसान रैली का हुआ असर, समस्याओं का निराकरण करेंगे सीधे एसडीएम

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बीजापुर, 23 जून। जिला मुख्यालय में सोमवार को हुई किसान रैली का असर नजर आ रहा है। खेती-किसानी का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो तथा किसानों को खाद, बीज, डीजल अथवा अन्य कृषि संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को आवश्यक निर्देश दिए हैं।कलेक्टर विश्वदीप ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा खेती-किसानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की है कि कृषि कार्य से जुड़े खाद बीज एवं डीजल की समस्या होने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम से सीधे संपर्क करें।

जिले के बीजापुर अनुभाग = एसडीएम, जागेश्वर कौशल - 9165989716, उसूर अनुभाग = एसडीएम भूपेन्द्र गावरे - 9584603977, भोपालपटनम अनुभाग - एसडीएम यशवंत नाग - 9329781207, भैरमगढ़ अनुभाग = एसडीएम विकास सर्वे - 8305418893 को संपर्क कर खाद, बीज, डीजल संबंधी किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल संबंधित एसडीएम को अवगत करें ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान से शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने विशेष ध्यान दें:कलेक्टर

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 23 जून। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समन्वित रूप से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित 31 व्यक्तिगत हितग्राहीमूलक योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण किया जाना है। अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाने के साथ-साथ नागरिकों का शासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान संबंधी दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन कर विभागवार कार्ययोजना तैयार करने तथा मैदानी स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि अभियान के प्रथम चरण में ग्रामवार आधारभूत आंकड़ों का संकलन एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद डाटा विश्लेषण के आधार पर चिन्हित पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम, क्लस्टर एवं विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों के आयोजन से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं तथा योजनाओं की पात्रता से संबंधित जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। कलेक्टर ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए।समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश देते हुए विशेष रूप से भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण पंचायत स्तर पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में अपेक्षित गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल उपलब्धता से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से प्रकरण लंबित न रखें जाएं तथा शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत प्रदान की जाए।कलेक्टर ने राज्य शासन, प्रभारी मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के जिले के भ्रमण के दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए चिप्स द्वारा विकसित किए जाने वाले सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड का उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्राम, पंचायत, विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर योजनाओं के संतृप्तिकरण की वास्तविक समय में समीक्षा की जा सकेगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी इस अभियान को मिशन मोड में लेते हुए पूरी प्रतिबद्धता और गंभीरता के साथ कार्य करें।

साल्हेवारा की बेटी हीना रजक ने एमएससी प्राणि विज्ञान में 81% अंकों के साथ रचा नया कीर्तिमान

■ संघर्ष, संस्कार और सफलता की मिसाल

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

साल्हेवारा 23 जून। वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा की होनहार बेटी हीना रजक ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवनशैली के बल पर दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव से एम.एससी. (प्राणि विज्ञान) की स्नातकोत्तर परीक्षा में 81 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे साल्हेवारा क्षेत्र एवं रजक समाज में हर्ष और गौरव का वातावरण है। हीना रजक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा साल्हेवारा में प्राप्त की। बचपन से ही वह पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद एवं अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रही हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर परिश्रम और परिवार का सहयोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। हीना की माता रेखा रजक एक कुशल गृहिणी हैं, जिन्होंने सदैव अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं उनके पिता मोहित रजक विद्यालयों में एक जागरूक एवं प्रेरणादायी पालक के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। परिवार के संस्कार और शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण ने हीना की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हीना के चाचा जमुना रजक, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में कंपनी कमांडेंट के पद पर भिलाई में पदस्थ हैं, दादा गोविंदराम रजक तथा दादी माया रजक ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हीना के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अपनी सफलता पर हीना रजक ने कहा कि उनका सपना सहायक प्राध्यापक बनकर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता-पिता के स्नेह, परिवार के सहयोग, कठिन परिश्रम और अनुशासित दिनचर्या को दिया।

हीना रजक की सफलता पूरे साल्हेवारा क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि ग्रामीण अंचल की बेटियाँ भी अपनी लगन और मेहनत के दम पर ऊँचाइयों को छू सकती हैं।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर दिलीप शुक्ला, ललित सोनी, बहादुर सिंह खुशरो, निजाम सिंह मंडावी, नरेन्द्र पटले, गिरधारी लाल वर्मा, जगदीश राम पंचकपाट, नेमबाई निर्मलकर, डॉ. अखिलेश यादव (सहायक प्राध्यापक) एवं धनीराम डड़सेना सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने हीना रजक को शुभकामनाएँ एवं बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएँ प्रेषित की हैं।

एक नजर

आल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में कु. लक्षिता राठी ने अंडर-13 वर्ग में पहला स्थान अर्जित किया

डोंगरगढ, 23 जून(तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। गोंदिया जिले में राय सोनी कल्पना वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट वा गोंदिया जिला शतरंज़ संघ द्वारा आयोजित आल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में 200 शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें डोंगरगढ की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त खालसा पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल डोंगरगढ की आठवी कक्षा की छात्रा शतरंज खिलाड़ी कु. लक्षिता राठी ने अंडर 13 वर्ग में पहला स्थान अर्जित किया इन्हें आयोजकों द्वारा ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, वा नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई है..नियमित पढ़ाई वा शतरंज खेल का अभ्यास करने वाली लक्षिता राठी शुरू से विभिन्न प्रतिस्पर्धाओ में भाग लेती आ रही है. इस वर्ष भी वह कई राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धाओं की तैयारियों में अभ्यासरत है .एन. आर. सी.ए. शतरंज संस्था के पदाधिकारी वा सदस्यों ने शुभकामनाएं दी वा उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

आयुक्त ने सुबह फ्लाई ओव्हर के नीचे साफसफाई का किया निरीक्षण

राजनांदगांव 23 जून(तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। प्रतिदिन सफाई निरीक्षण की कडी में नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा आज जी.ई.रोड फ्लाई ओव्हर के नीचे साफ सफाई का जायजा लेकर गंदगी फैलाने वालो पर जुर्माना लगाने के स्वास्थ्य अमला को निर्देश दिए। निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा आज सफाई निरीक्षण में भगत सिंह चैक फ्लाई ओव्हर के नीचे सफाई का जायजा लेकर उन्होंने होटल एवं ठेला के आस पास साफ सफाई रखने, कचरा फैलाने वालो पर कार्यवाही कर जुर्माना लगाने स्वच्छता निरीक्षक श्री दीपक श्रीवास्तव को निर्देशित किए। उन्होंने होटल एवं ठेला के पास गंदगी देख नराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित से कहा कि अतिक्रमण कर व्यवसाय न करे और साफ सफाई रखे, अन्यथा जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। साफ सफाई के अभाव में संबंधित से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। निर्देश के अनुक्रम में सूरज चाय ठेला से 5 सौ रूपये, के.जी.एन. पान सेन्टर एवं सिन्हा चाय ठेला से 2-2 सौ रूपये जुर्माना वसूला गया। आयुक्त ने आस पास के लोगो को साफसफाई रखने अतिक्रमण नही करने समझाईस दिए। आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य अमला से कहा कि जी.ई.रोड में शहर के अलावा बाहर के लोगो का भी आना जाना लगा रहता है, जहॉ से हमारे शहर की छवि प्रदर्शित होती है। इसलिए जी.ई.रोड में साफ सफाई रखे, नाली नालो की सफाई करे, रोड के किनारे के दुकानदारो व ठेला खोमचा वालो को साफ सफाई रखने समझाईस देवे, अतिक्रमण करते देख हटाने की कार्यवाही करे तथा संबंधितो पर जुर्माना लगावे। फ्लाई ओव्हर के नीचे भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए अतिक्रमण न होने दे।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

राजनांदगांव 23 जून। प्राथमिक शाला धामनसरा में सामूहिक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के योगासन पीटीआई शिक्षक संतोष देशमुख प्रधान पाठक रोहित साहू पूर्व जनपद सदस्य योगेंद्र दास वैष्णव सरपंच प्रतिनिधि कृतलाल पटेल शिक्षक उर्वशी चंद्राकर नीतू चौरासिया सीमा यादव ने प्रथामिक शाला छात्र छात्राओं को योग दिवस पर योगसन ताड़ासन वृक्षासन भुजंगासन पवनमुक्तासन प्रणायाम एवं अन्य योग अभ्यास कराया गया योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वास्थ् जीवनशैली है नियमित योग से तन मन स्वस्थ रहता हैं लोग प्रतिक्षमता बढ़ाती है योग दिवस हार्दिक शुभकामनाएं दी।

बोरतलाव थाना एक बार फिर मवेशियों को कट्टीपार कराए जाने के मामले में सुर्खियों में

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़ 23 जून। डोंगरगढ़ ब्लॉक का बोरतलाव थाना एक बार फिर मवेशियों को कट्टीपार कराए जाने के मामले में सुर्खियों में है। गांव के पंचों को कथित रूप से डराने-धमकाने के मामले के बाद अब पशु तस्करी के आरोपों से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर ग्रामीणों द्वारा पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर बोरतलाव पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, यह मामला 10 जून 2026 का बताया जा रहा है। ग्राम अंडी में ग्रामीणों ने एक पिकअप वाहन क्रमांक छ्त्त 08,रू 8068 को रोका था, जिसमें तीन भैंसें लदी हुई थीं। ग्रामीणों का आरोप है कि वाहन चालक के पास मवेशियों के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पूछताछ के दौरान चालक, जिसने अपना नाम सलीम खान बताया, ने वीडियो में कथित तौर पर वाहन और मवेशी परिवहन से जुड़ी कई जानकारियां साझा कीं।

ग्रामीणों द्वारा बनाए गए वीडियो में चालक यह दावा करता दिखाई दे रहा है कि वाहन डोंगरगढ़ निवासी मनोज श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव का है और इस वाहन से नियमित रूप से मवेशियों का परिवहन महाराष्ट्र की ओर किया जाता है। हालांकि वीडियो की सत्यता और उसमें किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। बताया जा रहा है कि वीडियो में नाम आने के बाद मनोज श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव ने घटना के लगभग एक सप्ताह बाद बोरतलाव थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में एक लाख रुपये दिए जाने और बाद में खाली वाहन मिलने जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया है।

इधर आज सोमवार को ग्राम अंडी के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में बोरतलाव थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आवेदन में वाहन के स्वामित्व, चालक की भूमिका, वीडियो में सामने आए तथ्यों और कथित पशु परिवहन नेटवर्क की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही जांच में आरोप सही पाए जाने पर छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम अंडी मार्ग से मवेशियों के अवैध परिवहन की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे में पुलिस को पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ानी चाहिए।

फिलहाल मामला शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर जांच के दायरे में है। अब देखना होगा कि बोरतलाव पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं। परंतु मामले में यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर इतनी बड़ी रकम के लेन देन के बाद मामले में बबलू श्रीवास्तव इतने दिनों तक क्यों चुप थे और अगर ग्रामीणों द्वारा भी बिना दस्तावेज के पशु परिवहन होते गाड़ी रोक ली गई तो पुलिस को मौके पर क्यों नहीं बुलाया गया या तत्काल शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई, वही सबसे गंभीर प्रश्न तो पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी घटना घटी परंतु थाना प्रभारी केवल आवेदन लेते ही नजर आते है, ऐसे में फिर एक बार बोरतलाव पुलिस थाना की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बोरतलाव, अंडी, पनियाजोब, खरखाटोला सहित आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों की माने तो डोंगरगढ़ से बोरतलाव की ओर रोजाना मवेशियों से लदी दर्जनों गाड़ियां महाराष्ट के लिए जाती हैं जो पुलिसिया मिली भगत के संभव नहीं है। हालांकि की इस बात की हम पुष्टि नहीं करते परन्तु ग्रामीणों द्वारा पुलिस के ऊपर लगाए आरोपों से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बताया जाता है कि डोंगरगढ़ के कुछ पशु तस्करों के संगठित गिरोह जो आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से मवेशियों की खरीदारी कर महाराष्ट भेजा जाता है। वहीं बताया जाता है कि महाराष्ट के एक स्थान से इन पशुओं की नीलामी की जाती है उसके बाद एक विशेष वर्ग के द्वारा पशुओं को काटने ले जाया जाता है। वहीं बताया जाता है कि इस रैकेट में एक विशेष वर्ग के अलावा हिंदू लोग भी शामिल है जो इसे अपना कारोबार समझते है।

ग्राम पंचायत में स्वच्छता चौपाल का आयोजन,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर गंभीर चर्चा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 23 जून। कलेक्टर कुलदीप शर्मा महोदय के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्वच्छता चौपाल का आयोजन जिले में सोमवार से शुरू हुआ। प्रत्येक जनपद पंचायत में प्रतिदिन 5 ग्राम पंचायत में स्वच्छता चौपाल का कार्यक्रम किया जाएगा। स्वच्छता चौपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर विशेष चर्चा ग्रामीणों से किया जा रहा है। इसमें चार प्रकार के कचरे को घर स्तर पर ही अलग-अलग करना, सेग्रीगेशन शेड में ले जाकर अलग हुए कचरे को अलग अलग ही पैक कर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तक पहुंचाना, रिसाइकलर या कबाड़ी वाले को बेचना किसी भी प्रकार के पॉलिथीन को जलने पर मना करना, लोगों को समझाइश देना शामिल है। इसके साथ ही यूजर चार्ज लिए जाने पर भी चर्चा किया जा रहा है। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिये कचरे का ढेर कम से कम हो,ठोस कचरे का प्रबंधठु और महत्व हमारे जीवन में यह क्या महत्व पर विस्तृत रूप से स्वच्छता चौपाल में चर्चा किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जे. बी. इंटरनेशनल स्कूल एवं जे. बी. पब्लिक स्कूल में उत्साह से मनाया गया

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

तिल्दा-नेवरा,23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जे. बी. एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत संचालित जे. बी. इंटरनेशनल स्कूल एवं जे. बी. पब्लिक स्कूल में योग, स्वास्थ्य एवं जागरूकता पर आधारित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए योग को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का आधार बताया।

जे. बी. इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित विशेष योग सत्र की मुख्य अतिथि एवं प्रशिक्षक सुश्री नीलिमा कुजूर थीं। उन्होंने विद्यार्थियों को योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों की जानकारी देते हुए बताया कि नियमित योगाभ्यास तनाव कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा मानसिक शांति प्रदान करता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट योग एवं प्राणायाम करने की सलाह दी। योग सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने सुखासन, वज्रासन, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, सेतु बंधासन, पवनमुक्तासन, पद्मासन तथा सूर्य नमस्कार सहित अनेक योगासनों का अभ्यास किया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।

वहीं, जे. बी. पब्लिक स्कूल में योग प्रशिक्षक सुश्री मुस्कान बत्रा ने विद्यार्थियों को योग के महत्व, विभिन्न आसनों तथा दैनिक जीवन में योग को अपनाने के लाभों के बारे में मार्गदर्शन दिया। योग दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में इंटर-हाउस पोस्टर मेकिंग एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टरों एवं प्रभावशाली नारों के माध्यम से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन का संदेश दिया। विद्यालय का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, सशक्त मन और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण भी है। इसी दृष्टिकोण के साथ विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शैक्षणिक, खेल, कला एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को समान महत्व देता है। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। यह आयोजन स्वास्थ्य, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में सफल रहा।

प्रदेश के सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला शामिल

■ जिले के सभी ग्रामो में 31व्यक्तिमूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को किया जाएगा लाभान्वित

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 23 जून। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश के 23 जिलों में शुरू होने वाले इस अभियान में जिला बलौदाबाजार -भाटापारा भो शामिल है।इस अभियान के तहत जिले के सभी गांव में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण का व्यापक कार्यक्रम होगा, जिसके माध्यम से योजनाओं की पहुंच, प्रभावशीलता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी। सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जाएगा।

'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान का मूल उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र हितग्राहियों तक उनका शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है। 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण स्थापित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा, जिसमें योजनाओं की जानकारी, पात्रता, प्रगति और संतृप्तिकरण की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध होगी।

31 जनकल्याणकारी योजनाओं का होगा संतृप्तिकरण-अभियान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़ी 31 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है।इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, महतारी वंदन योजना, जन-धन योजना, कौशल विकास योजनाएं, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा, आधार कार्ड तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं शामिल हैं।इन योजनाओं का उद्देश्य परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के अवसर उपलब्ध कराना है।

तीन चरणों में होगा अभियान का संचालन-अभियान का क्रियान्वयन सुव्यवस्थित रूप से तीन चरणों में किया जाएगा।पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण एवं डेटा मानचित्रण किया जाएगा। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी।दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर एवं विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।तीसरे चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

बिजली, गैस, पेट्रोल और शराब को बनाया कमाई का जरिया, जनता पर बढ़ी महंगाई की मार : संदीप सोनी

राजनांदगांव 23 जून। युवा कांग्रेस शहर उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष संदीप सोनी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पिछले ढाई वर्षों में बिजली, रसोई गैस, पेट्रोल और शराब के माध्यम से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है और सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय राजस्व बढ़ाने में लगी हुई है। श्री सोनी ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिजली बिल, गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिक आज अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे बिजली कार्यालय, गैस एजेंसी तथा पेट्रोल पंपों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर वर्ष दो करोड़ रोजगार देने के वादे का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।

मुस्लिम समाज ने बहादुर अली को दी जन्मदिन की मुबारकबाद

राजनांदगांव 23 जून। जामा मस्ज़िद के मीडिया प्रभारी सैय्यद अफ़ज़ल अली ने बताया कि आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति बहादुर अली के जन्मदिवस पर शहर मुस्लिम समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों, कमेटी सदस्यों, बुद्धिजीवियों एवं युवाओं ने उन्हें पुष्पहार पहनाकर जन्मदिन की मुबारकबाद दी तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घ जीवन की कामना की। मुस्लिम समाज द्वारा आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रदेश के ख्यातिप्राप्त उद्योगपति जनाब बहादुर अली साहब का जन्मदिवस बड़े उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर शहर जामा मस्जिद (शहर ऐतराफ) जामा मस्ज़िद के सदर जनाब रईस अहमद शकील साहब द्वारा प्रेषित फूलों की लंबी संयुक्त माला पहनाकर बहादुर अली साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की गई। समारोह में मुस्लिम समाज के नौजवानों, बुजुर्गों, मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों, कमेटी सदस्यों एवं समाज के प्रबुद्धजनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

सांसद बृजमोहन ने रायपुर-धमतरी रेल लाइन को कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर से जोड़ते हुए विशाखापट्टनम तक विस्तार की मांग की

रायपुर 23 जून। नई दिल्ली में सोमवार को एस्टीमेट कमेटी की बैठक में रायपुर सांसद एवं समिति सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण योजना पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को मजबूती से उठाया। रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित योजनाओं की प्रस्तुति के बाद सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के विकास और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव समिति के समक्ष रखे।

बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब लंबे समय से प्रतीक्षित ÷रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना बस्तर क्षेत्र के विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए दुर्ग-पुरी तथा रायपुर-अंबिकापुर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ करने की मांग रखी। साथ ही बिलासपुर से नई दिल्ली के बीच संचालित राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। साथ ही उन्होंने रायपुर-धमतरी रेल लाइन को कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर होते हुए विशाखापट्टनम तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखते हुए इसे क्षेत्रीय विकास और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के सात राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन सभी राज्यों के साथ रेल संपर्क को और मजबूत किया जाना चाहिए। सांसद अग्रवाल ने रेलवे भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे जरूरतमंद परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने तथा इसके लिए उपयुक्त भूखंड चिन्हित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ मानवीय दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

बैठक में उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों को आधुनिक तकनीक और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया। इसके साथ ही रायपुर स्थित वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की आवश्यकता भी बताई।

उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य में जहां-जहां नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, वहां केवल माल परिवहन ही नहीं बल्कि यात्री परिवहन को भी समान प्राथमिकता दी जाए, ताकि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

सांसद अग्रवाल ने कोरोना काल से पूर्व जिन प्रमुख ट्रेनों का ठहराव तिल्दा, भाटापारा सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होता था, उन्हें पुनः बहाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी और क्षेत्रीय व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रायपुर शहर के तेजी से बढ़ते विस्तार का उल्लेख करते हुए सांसद श्री बृजमोहन ने रेलवे की भूमि से सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूआरएस और आरवीएच कॉलोनी क्षेत्र में सड़क निर्माण से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सकेगी। बैठक में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषयों को छत्तीसगढ़ के विकास, बेहतर रेल संपर्क, यात्री सुविधाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धमतरी (छ.ग.)

निविदा निरस्तीकरण

जी-क्रमांक-262700440

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना क्रमांक-01/ले.शा./का.अ./लो.स्वा.यां./2026-27 धमतरी दिनांक-28.04.2026, सिस्टम नम्बर 189900 जिसका (**जी.क्रमांक-262700440**) को आमंत्रित की गई निविदा अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
धमतरी (छ.ग.)

जी- 262701610/5

एक नजर

आलोक कुमार ने संभाला पदभार

रायपुर, 23 जून। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ में आज आलोक कुमार, महाप्रबंधक तकनीकी ने क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने विधिवत रूप से कार्यभार संभालते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इससे पूर्व वे नई दिल्ली मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। निवर्तमान क्षेत्रीय अधिकारी आर. वेंकटेश्वरलु के पटना स्थानांतरण के बाद आलोक कुमार की रायपुर पदस्थापना हुई है।

29 जून को मटन विक्रय बंद

रायपुर, 23 जून। 29 जून को कबीर जयंती के मौके पर रायपुर में मांस-मटन खाने की प्लानिंग है तो पहले ये खबर पढ़ लीजिए। रायपुर नगर निगम ने पूरे शहर में मांस-मटन की बिक्री और बूचड़खानों के संचालन पर एक दिन के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। नगर निगम के आदेश के मुताबिक 29 जून को शहर की सभी मांस-मटन दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फदुकानें ही नहीं, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। निगम ने साफचेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफसख्त कार्रवाई होगी। मौके पर सामान जब्त किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

रेल यात्रियों की सुरक्षा उपायों की जांच

रायपुर, 23 जून। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में 22 जून को रेलवे बोर्ड के महानिदेशक संरक्षा हितेंद्र मल्होत्रा द्वारा सेफ्टी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रायपुर दयानंद सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। हितेंद्र मल्होत्रा ने कोचिंग डिपो दुर्ग में यात्री गाड़ियों की मेंटेनेंस व्यवस्थाओं के सेफ्टी पहलुओं का निरीक्षण किया कोचिंग डिपो दुर्ग में ट्रेनों के शंटिंग की सावधानियां, फायर डिटेक्शन सिस्टम, की सभी प्रमुख लाइन स्टाफ को जानकारी। विभागीय संसाधनों से निर्मित फीबा टेस्ट स्टैंड जो ट्रेन के पाट्र्स की जांच करती है। फायर डिटेक्शन सिस्टम मॉडल की कार्यविधि, ट्रेन के कोचों की इंटरमीडिएट ओवरहालिंग शॉप शेड्यूल की जांच की। दुर्ग लॉबी में लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर के ट्रेन परिचालन के संरक्षा नियमों पर चर्चा की एवं लॉबी की व्यवस्थाओं को देखा एवं क्रू मेंबर्स के प्रशिक्षण पर जोर दिया।

सीए सिंघानिया ने ट्रिब्यूनल में दिया व्याख्यान

रायपुर, 23 जून। रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन द्वारा आज जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की प्रक्रिया एवं ड्राफ्टिंग विषय पर एक महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आदित्य सिंघानिया थे। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह रहा कि मात्र 22 वर्ष की आयु में सीए आदित्य सिंघानिया ने रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन जैसे प्रतिष्ठित संगठन के मंच से अपना प्रथम व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील प्रस्तुत करने की संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, समय-सीमाओं, ड्राफ्टिंग की बारीकियों तथा विभिन्न व्यावहारिक एवं तकनीकी पहलुओं की जानकारी अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीएसटी बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भाविक शाह ने की। संचालन सचिव प्रवीण शर्मा द्वारा किया गया तथा उपाध्यक्ष मनीष बजाज ने आभार प्रदर्शन किया।

सेंट पॉल स्कूल के विवादित भवन पर चला बुलडोजर

रायपुर, 23 जून। सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने एक विवादित सामुदायिक भवन पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वदिनी पांडेय ने सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च बनाए जाने का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

बता दें कि सेंट पॉल स्कूल के पास बने विवादित भवन को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान स्थिति न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने सेंट पॉल स्कूल के दोनों तरफकी सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। मौके पर अपर कलेक्टर, एडीसीपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

चर्च बनाने का आरोप

इस पूरे मामले में हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वदिनी पांडेय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है सेंट पॉल स्कूल परिसर एक शैक्षणिक संस्थान है। सेंट पॉल ट्रस्ट के पास इस जमीन की लीज़ साल 2022 में ही खत्म हो चुकी है। लीज़ समाप्त होने के बावजूद स्कूल परिसर में सामुदायिक भवन के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण के लिए न तो ट्रस्ट के पास परमिशन थी और न ही नगर निगम को इसकी कोई जानकारी दी गई थी। वही उन्होंने आगे कहा कि हमारी शिकायत को शासन-प्रशासन ने सही पाया।

तालाब बचाने के लिए आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

रायपुर, 23 जून। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने सरोवर हमारी धरोहर को प्रदेश सरकार का खोखला नारा बताते हुए कहा कि शहर के तालाबों को लगातार को माफिया निगलते जा रहे हैं। सरकार के संरक्षण में तालाब और पैठू को खत्म करने का काम लगातार जारी है। प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने उपवसाय का एक ज्ञापन नगर निगम आयुक्त समित मिश्रा के नाम पर निगम कार्यालय में सोप आयुक्त से उन्होंने निवेदन किया कि रायपुर शहर जो कि तालाबों का शहर था इस शहर के बचे खुचे तालाब को बचना होगा हमेशा जल स्रोत बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि महाराजबंध तालाब के पाटे जाने की खबर लगातार प्रकाशित हो रही है इससे पूर्व बूढ़ा तालाब और अन्य तालाबों को बेदर्दी से छोटा किया गया है। विपिन बिहारी सुर वार्ड के अंतर्गत कैलाशपुरी गभरापारा के बीच स्थित डबरी तालाब को मलबा डालकर पाटने का षड्यंत्र लगातार चल रहा था जिसे एक बार मेरे द्वारा रोका गया था। वर्तमान में तालाब में जाने का मुख्य रास्ता जो कैलाशपुरी से है उसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। तालाब पर कब्जे की साजिश के अंतर्गत तालाब में जाने के रास्ते को बंद किया गया है। इस संबंध में आसपास के लोगों से चर्चा करने पर किसी भी तरह से तालाब में गेट लगाने वालों के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तालाब के रास्ते पर किसके द्वारा गेट लगाकर बंद किया गया है।

PICTURE-स्टोरी

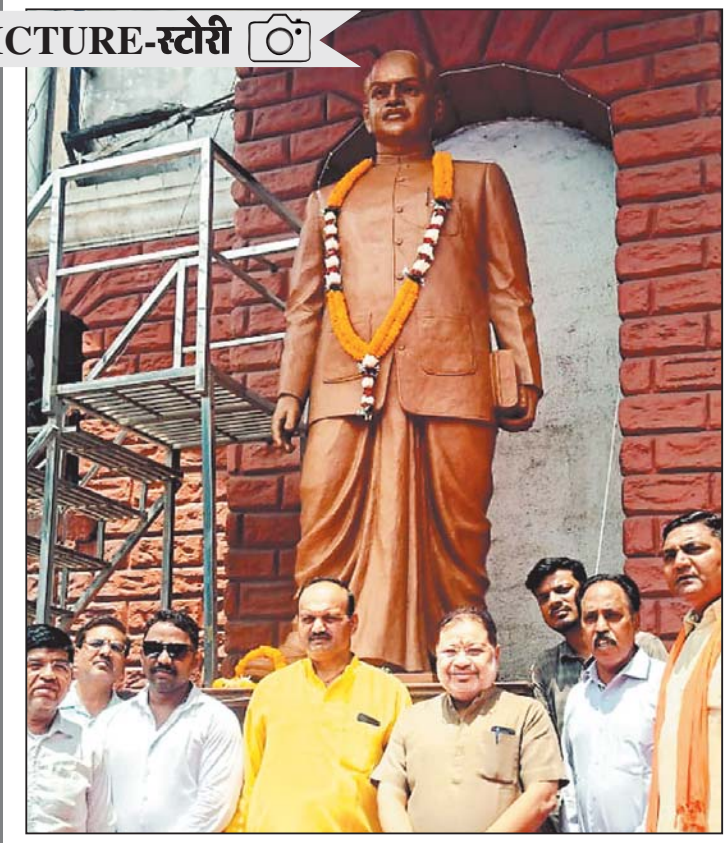

रायपुर, 23 जून। विधायक सुनील सोनी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

युवक की हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 23 जून। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित डब्ल्यूआरएस कॉलोनी मैदान में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, 21-22 जून की दरमियानी रात खमतराई थाना क्षेत्र के डब्ल्यूआरएस कॉलोनी मैदान में अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा खमतराई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी और मुखबिर तंत्र की मदद से दो आरोपियों तुषार सोनी और पीयूष मानिकपुरी को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वे शराब के नशे में थे। इसी दौरान मृतक के साथ हुए क्षणिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और उन्होंने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफहत्या सहित संबंधित धाराओं के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

12 हजार मनरेगा कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान

रायपुर, 23 जून। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों के आंदोलन की आहट तेज हो गई है। एचआर पॉलिसी, सेवा सुरक्षा और ग्रेड पे सहित लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ ने 2 जुलाई 2026 से चरणबद्ध हड़ताल का ऐलान किया है। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की रविवार को आयोजित प्रदेश स्तरीय वर्चुअल बैठक वीसी, में बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में प्रांतीय, संभागीय, जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्य शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 1 जुलाई 2026 तक कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की जातीं, तो 2 जुलाई से प्रदेश के करीब 12, 000 कर्मचारी चरणबद्ध हड़ताल पर चले जाएंगे।

» 2 जुलाई से तीन चरणों में होगा बड़ा आंदोलन

एचआर पॉलिसी और लंबित मांगें प्रमुख मुद्दा: कर्मचारियों का आरोप है कि ढाई वर्षों से एचआर पॉलिसी की फाइल लंबित पड़ी है। इसके लिए गठित समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। महासंघ का कहना है कि बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद ग्राम रोजगार सहायकों को पूर्व की भांति संविदा पर रखने, ग्रेड पे निर्धारण और सेवा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं की गई।

राज्यपाल ने रोटरी क्लब ग्रेटर के सेवा कार्यों को सराहा

रायपुर, 23 जून। रोटरी क्लब ग्रेटर रायपुर के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर समाज हित और जन-कल्याण से जुड़े विविध महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान, राज्यपाल डेका ने रोटरी क्लब द्वारा संचालित विभिन्न समाज कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह क्लब सेवाभाव से प्रेरित एक सुव्यवस्थित और समर्पित संगठन है। सामूहिक प्रयासों की महत्ता पर बल देते हुए, उन्होंने ने कहा कि समाज के समग्र विकास और जन-कल्याण के लक्ष्यों को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब सभी संस्थाएं और नागरिक एकजुट होकर साथ कार्य करें। इस बैठक में राज्यपाल ने सामाजिक उत्थान और सामुदायिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिनिधिमंडल को अपना मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

इससे पूर्व, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रितेश जिंदल ने राज्यपाल का स्वागत किया। क्लब की ओर से सम्मान स्वरूप उन्हें एक स्मृति चिह्न भी भेंट किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, रोटरी क्लब ग्रेटर रायपुर के सचिव प्रकाश अग्रवाल सहित क्लब के अन्य विशिष्ट पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।

संविदा कर्मचारी जारी रखेंगे आंदोलन

रायपुर, 23 जून। पॉवर कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के विषय पर चर्चा हेतु सक्षम अधिकारी अध्यक्ष, छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, द्वारा संघ को समय प्रदान न करने से निराश, आहत होकर 'अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अभिषेक वर्मा प्रदेश प्रवक्ता राहुल चौबे क्षेत्रीय अध्यक्ष गण तपन राम पैंकरा अंबिकापुर क्षेत्र, विजय प्रकाश बंजारे बिलासपुर क्षेत्र, नंद कुमार मरकाम रायगढ़ क्षेत्र, जीवराज सोनकर रायपुर शहरी क्षेत्र, वीर सिंह बरेठ रायपुर ग्रामीण क्षेत्र, अनिल दिवाकर दुर्ग क्षेत्र, संदीप गजेंद्र राजनांदगांव क्षेत्र, खेमलाल बधमरिया पारेषण कंपनी, देवेंद्र शार्दुल महामंत्री, जगदलपुर क्षेत्र ने आज पत्रवार्ता में बताया कि पॉवर कपनी में कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण मांग नियमितिकरण, रिक्त पदों पर समायोजन/संविलियन के परिप्रेक्ष्य में छ.वि.सं.कर्म. संघ 722, का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पूर्व में इसी पॉवर कंपनी में तत्कालीन सत्ताधीश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन काल 7 में सत्र 2007, 2009, 2011 में संविदा पद पर भर्ती लिया गया था जिन्हें कंपनी प्रबंधन द्वारा दो वर्ष पश्चात् क्रमशः सत्र 2009, 2011, 2013 में, नियमितिकरण किया गया था, किंतु सत्र 2016 और 2018 में संविदा पद पर भर्ती किए गए कर्मचारियों को क्रमशः 10 वर्ष और 08 वर्ष पूर्णता की ओर अग्रसर हैं किंतु आज पर्यंत तक संविदा कर्मचारी के रूप में शोषित किया जा रहा है, जबकि पॉवर कंपनी में विद्युतीय रखरखाव का कार्य स्थायी प्रकृति का होता है। पॉवर कंपनी में नियमित कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसकी पूर्ति हेतु कंपनी प्रबंधन संविदा कर्मचारियों का शोषण कर रही है। मांगे पूरी न होने तक पॉवर कंपनी में कार्यरत विद्युत संविदा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन जारी रहेगा।

निर्माण व जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गति देने के दिए निर्देश

रायपुर, 23 जून। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने नगरीय निकायों के कार्यों की मॉनिटरिंग व समन्वय के लिए जिलेवार नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में निर्माण और जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गति देने सक्रियता एवं गंभीरता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों की समस्याओं का हल निकालकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में मैदानी निरीक्षण के दौरान वहां की जरूरतों और व्यवस्थाओं का आकलन भी करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव शंगीता आर. ने बैठक में नोडल अधिकारियों से उनके नगरीय निकायों के भ्रमण और बैठकों का फीडबैक लेकर निकायों में कार्यों की वस्तुस्थिति जानी। उन्होंने कहा कि निकायों में कार्यों के निरीक्षण के लिए पूरी तैयारी से जाएं। विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितनी राशि जारी की गई है, इसकी भी जानकारी रखें। उन्होंने निकायों में प्रगतिरत निर्माण कार्यों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए।

श्रीमती शंगीता आर. ने नोडल अधिकारियों को आबंटित जिले के आय-व्यय की स्थिति पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो निकाय खुद की आय से अपनी सभी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें।

आनंदवन में बुजुर्गों ने किया योग और व्यायाम

रायपुर, 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ग्राम गोमची स्थित माँ गोदावरी आनंदवन आश्रम में वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्ग माता-पिता के लिए विशेष योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आश्रम में निवासरत सभी बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए योग, प्राणायाम एवं विभिन्न व्यायामों का अभ्यास किया। इस अवसर पर आश्रम के ट्रस्टी योगेश तिवारी ने स्वयं उपस्थित होकर बुजुर्गों को योगाभ्यास कराया तथा उन्हें नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बुजुर्गों को सरल योगासन, प्राणायाम, श्वास संबंधी व्यायाम एवं स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों का अभ्यास करवाया।

योग सत्र के दौरान बुजुर्गों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में योगेश तिवारी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति और ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित रखने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। नियमित योग करने से व्यक्ति तनावमुक्त रहता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है तथा अनेक शारीरिक और मानसिक समस्याओं से बचाव होता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए योग अत्यंत लाभकारी है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में होने वाली कई समस्याओं को योग एवं प्राणायाम के माध्यम से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। योग शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। योगेश तिवारी ने कहा कि माँ गोदावरी आनंदवन आश्रम में निवासरत सभी बुजुर्ग हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनका स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है।

समारोह | **एरोबैटिक योग के हैरतअंगेज प्रदर्शन और सिंगर धीरज के संगीत का चला जादू**

51 योग गुरुओं का हुआ सम्मान

योग ऋषियों-मुनियों की दी गई अमूल्य धरोहर : थौरानी

कार्यक्रम में चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने सभी को योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि, योग हमारे ऋषियों-मुनियों द्वारा दी गई वह अमूल्य धरोहर है, जो हमारे शरीर को निरोग, बुद्धि को प्रखर और मन को शांत रखती है। यदि हमारा व्यापारी वर्ग और आम नागरिक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा व्यापार उन्नत होगा और तभी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य और देश प्रगति के पथ पर समृद्ध बनेगा। चेम्बर इस भव्य आयोजन के माध्यम से सभी से योग को अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील करता है। चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी, राधा किशन सुंदरानी एवं जसप्रीत सिंह सलूजा ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि रायपुर के मैग्नेटो मॉल में आयोजित योग लेजेंड्स समारोह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में चेम्बर का एक ऐतिहासिक कदम है। व्यापार और उद्योग जगत की व्यस्त दिनचर्या के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

रायपुर, 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर कल शाम छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं छत्तीसगढ़ योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर के मैग्नेटो मॉल, रायपुर में भव्य योग लेजेंड्स समारोह का सफल आयोजन मीनल चैबे, महापौर के मुख्य आतिथ्य में एवं अनामिका सिंह पार्षद एवं एमआईसी सदस्य, नगर पालिक निगम रायपुर के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम में चेम्बर के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध जनों, योग साधकों और आम नागरिकों ने बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाया और योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह में समाज को निस्वार्थ भाव से स्वस्थ रखने और योग को जन-जन तक पहुँचाने वाले प्रदेश के 51 महान योग विशेषज्ञों व गुरुओं का भव्य सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ चेम्बर और छत्तीसगढ़ योगासना स्पोर्ट्स के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में उपस्थित योग विभूतियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पेशेवर योग साधकों द्वारा प्रस्तुत किए गए एरोबैटिक योग ने दर्शकों को अत्यंत रोमांचित किया। हवा में अद्भुत संतुलन बनाते हुए साधकों ने कठिन आसनों का प्रदर्शन किया उसके साथ अत्यंत जटिल पार्टनर योग शामिल थे। शरीर की कल्पनीय लचीलेपन और एकाग्रता के इस अद्वितीय समन्वय को देख पूरा मॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, सलाहकार-सरल मोदी, मोहनलाल तेजवानी, कार्यकारी अध्यक्ष-राधाकिशन सुन्दरानी, राजेश वासवानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, कार्यकारी महामंत्री कपिल दोशी, उपाध्यक्ष-दिलीप इसरानी, मनीष प्रजापति, सुदेश मध्यान, जितेन्द्र बड़वानी, राजेश गुरनानी, मंत्री-प्रशांत गुप्ता, राजेन्द्र पारख, आलोक शर्मा, गुलाबचंद्र साहू, संदीप मेघानी, सांस्कृतिक प्रभारी अनिल जोतसिंघानी, सदस्य- निखिल पंड्या, महिला चेम्बर अध्यक्ष डॉ. ईला गुप्ता, कोषाध्यक्ष नम्रता अग्रवाल, हेमल शाह, सहित अनेक चेम्बर पदाधिकारी एवं व्यापारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

लायंस शिखर की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

रायपुर, 23 जून। लायंस क्लब रायपुर शिखर की नई कार्यकारिणी ने 21 जून को शपथ ली। प्रभा मंथा अध्यक्ष बनाई गई हैं। जबकि दविन्दर ग्रेवाल और किरण बाला खलको क्रमशः सचिव और कोषाध्यक्ष हैं। क्लब ने दतरेंगा में करीब ढाई हजार वर्ग फीट में वृद्धा आश्रम के निर्माण में तेजी लाने पर बल दिया। क्लब ने बताया कि दतरेंगा स्थित योजना अपने आप में अनोखी योजना है जिसके पूरे होने के लिए बहुतों को इंतजार है। कार्यक्रम में शपथ अधिकारी ने 12 नये सदस्यों को शपथ दिलाई। लायंस क्लब शिखर की स्थापना के 12 साल पूरे हो गए हैं।

क्लब की चार्टर प्रेसीडेंट लायन सरोज पांडेय ने बताया कि यहां वृंदावन भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीएमजेएफ पूर्व गवर्नर तिलोक चंद बरड़िया, शपथ अधिकारी पूर्व प्रांतपाल लायन प्रीतपाल बॉली, विशिष्ट अतिथि द्वितीय गर्वनर लायन अनिल पटेल, रीजन चेयरमेन रेणु गुप्ता, जोन चेयरमेन मीनाक्षी भार्गव एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरोज पांडेय ने अवगत कराया कि प्रत्येक वर्ष नवीन कार्यकारिणी का गठन बड़े ही उमंग और उत्साह के शपथ विधि कराई जाती है। इस अवसर पर वर्ष 25-26 की अध्यक्ष उषा शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

कौशल किशोर मिश्र प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी की ओर से तरुण छत्तीसगढ़, तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस टॉवर, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं प्रकाशित प्रधान संपादक- कौशल किशोर मिश्र, पंजी. क्रं. 45088/85 डाक पं.छ.ग./रायपुर संभाग/33/2024-26